https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'कोई स्थान ऐसा नहीं रहेगा, जहां भाजपा न हो'

वर्ष-12, अंक-17, 01-15 सितंबर, 2017 (पाक्षिक) ₹20

'न्यू इंडिया' की ओर...

उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय
एक बार में तीन तलाक की प्रथा खत्म

सुशासन की संवाहक:
मजबूत सांख्यिकीय प्रणाली

सर्वे संतु निरामया: को
चरितार्थ करती मोदी सरकार

मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के प्रवास की छवियां

भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए

बेंगलुरु में अपने आगमन के दौरान जनाभिवादन स्वीकार करते श्री अमित शाह

भोपाल में पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करते हुए

बेंगलुरु में नानाजी देशमुख पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए

भोपाल में संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए

बेंगलुरु स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में नानाजी देशमुख ई-पुस्तकालय के उद्घाटन के दौरान

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **न गाली से, न गोली से, परिवर्तन होगा गले लगाने से: नरेन्द्र मोदी**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को 71वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली समस्त महान...

वैचारिकी

हमारी नीति का लक्ष्य 'प्रत्येक को काम' मिलना चाहिए 16

श्रद्धांजलि

आचार्य विनोबा भावे 18

लेख

सर्वे संतु निरामयाः को चरितार्थ करती मोदी सरकार 23

देश बदलने की कोशिश 24

सुशासन की संवाहकः मजबूत सांख्यिकीय प्रणाली 26

तीन तलाक का खात्मा 29

भारत की बदलती तस्वीर देखने का अधिकार 30

अन्य

इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह के लिए फास्ट टैग की उपलब्धता सुगम करने हेतु उठाए गए कई कदम 14

'स्वस्थ बच्चे-स्वस्थ भारत' कार्यक्रम का शुभारंभ 17

एक बार में तीन तलाक की प्रथा खत्म 19

कोई स्थान ऐसा नहीं रहेगा, जहां भाजपा न होः अमित शाह 20

दीर्घकालीन सिंचाई निधि के लिए 9020 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी 25

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का भाषण 32

संगठनात्मक गतिविधियां

09 **'भ्रष्टाचारियों को संरक्षित और पोषित करती है सिद्धारमैया सरकार'**

एक बहुदलीय लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में किसी भी पार्टी का मूल्यांकन...

12 **नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार जीत**

हाल ही में तीन राज्यों-मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र-में संपन्न हुए नगरीय...

सरकार की उपलब्धियां

13 **सरकार ने घुटना प्रत्यारोपण के उच्चतम मूल्य निर्धारित किए**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2017 के अवसर पर दिए गए भाषण में की...

15 **माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अव्यपगत पूल के निर्माण की मंजूरी**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 16 अगस्त को 'माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

लोकतंत्र मत-पत्र तक सीमित नहीं हो सकता। तंत्र से लोक नहीं, बल्कि लोक से तंत्र...ऐसा लोकतंत्र, ऐसा न्यू इंडिया हमें बनाना है।

@AmitShah

क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख करना मोदी सरकार की पिछड़े वर्गों के आरक्षण और अन्य योजनाओं के विस्तार की दिशा में एक सार्थक पहल है।

@rajnathsingh

हमारी सेना और सुरक्षा के जवानों में वह दमखम है कि वे देश की सुरक्षा पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे।

@KailashOnline

योग्यता को समर्थन, 3.7 लाख स्कूली और 3.30 लाख कॉलेज के प्रतिभाशाली छात्रों को स्कालरशिप प्रदान की गई।

facebook

आवश्यकता है कि हमारे युवा एक सकारात्मक सोच के साथ, सच्ची निष्ठा, लगन व ईमानदारी के साथ, पूरे जुनून के साथ राजस्थान को देश का सिरमौर बनाने में जुट जाएं। हम सब मिलकर एक नए राजस्थान का निर्माण कर सकते हैं और करके ही रहेंगे!

— वसुंधरा राजे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नेपाल की नदियों पर बांध बनाकर बिहार में बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकालने पर भी बातचीत की। 1 अरब डालर के सहयोग के समझौते हुए।

— सुशील कुमार मोदी

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का हम स्वागत करते हैं, इसके माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला।

— योगी आदित्यनाथ

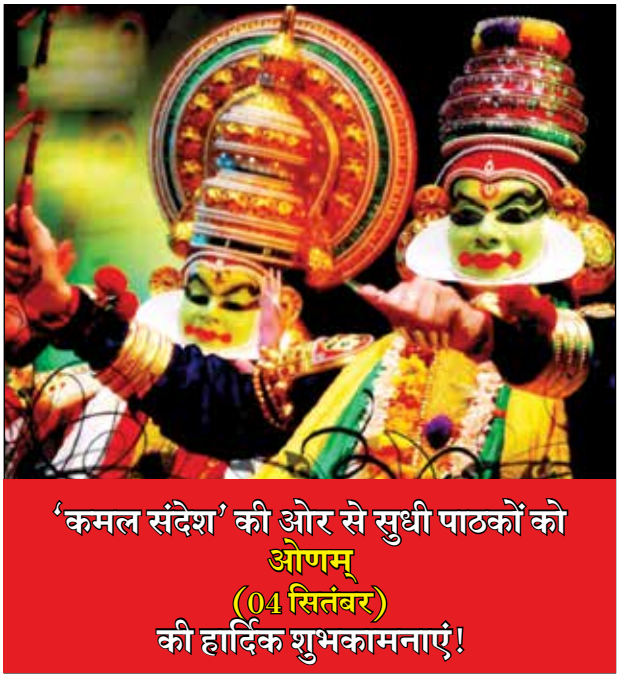

'राष्ट्र की सामूहिक इच्छा' का आह्वान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 71वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र संबोधन से देश फिर एक बार अपने उज्ज्वल भविष्य के प्रति आश्वस्त हुआ है। प्रधानमंत्री के शब्द हर भारतीय की आकांक्षाओं की प्रतिध्वनि है, जो भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाते हुए देखना चाहते हैं। परिवर्तन की बयार जो देश के कोने–कोने में महसूस की जा रही है, अब चहुंओर परिणाम दे रही है। साढ़े तीन वर्ष पूर्व की स्थिति– पॉलिसी पैरालिसिस, घोटाले, भ्रष्टाचार, कुशासन और हर ओर विफलता से देश अब उबर चुका है। देश तीव्र विकास के रास्ते पर है। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के साथ–साथ भ्रष्टाचार, कालेधन और आतंकवाद पर कठोर कदम उठाया गया है। यही नहीं, अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार, सीमाओं की समुचित रक्षा तथा मजबूत अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा से लोगों में भरोसा बहाल हुआ है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब बेहतर भविष्य के प्रति आशान्वित हैं। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी भारत के लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और राष्ट्र को अपने सम्बोधन में उन्होंने फिर से बदली मानसिकता का संदेश देते हुए 'बदल सकता है' के सकारात्मक रुख का संदेश दिया।

लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को चौथी बार सम्बोधित करते हुए उन्होंने लगभग हर विषय पर अपनी बात कही और नए भारत के दृष्टिकोण को सामने रखा। पिछले तीन वर्षों में नए सुधारों को साथ आगे बढ़ते हुए जनोपयोगी नीतियों और कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन किया गया। विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसे उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा व पहुंच के लिए हम बेहतर स्थिति में है। उपलब्धियां बेशुमार हैं– ओआरओपी के सफल कार्यान्वयन के साथ जनधन और उज्ज्वला योजना को भारी सफलता मिल रही है। सुरक्षा मोर्चे पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे उपायों के राष्ट्रीय भरोसे को बढ़ावा मिला है और सुरक्षा बलों को भारी सफलता मिल रही है। प्रधानमंत्री ने काली अर्थव्यवस्था पर भी प्रहार किया और देश में कालेधन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु बनाए गए कई कठोर कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने गरीबों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्रतिबद्धता बताया और कहा कि वे लगातार कालेधन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अपने भाषण में 'सहकारी संघवाद' से लेकर 'प्रतियोगी सहकारी संघवाद' के विचार को रखते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों को विकास के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता में लगे रहना चाहिए।

पिछले तीन वर्षों में नए सुधारों को साथ आगे बढ़ते हुए जनोपयोगी नीतियों और कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन किया गया। विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसे उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा व पहुंच के लिए हम बेहतर स्थिति में है। उपलब्धियां बेशुमार हैं– ओआरओपी के सफल कार्यान्वयन के साथ जनधन और उज्ज्वला योजना को भारी सफलता मिल रही है।

आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा जम्मू-कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 'न गाली से, न गोली से, परिवर्तन होगा गले लगाने से। अतएव वे चाहते हैं कि कश्मीरी राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हों। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत की नई वैश्विक छवि और मजबूत बने, ताकि काले धन और आतंकवादी गतिविधियों समेत महत्त्वपूर्ण सूचनाएं बेहतर ढंग से साझी की जा सकें। तमाम उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने सही अर्थों में 'सुराज' के लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान किया।

उन्होंने नए भारत के विजन को बार–बार सामने रखा। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए पक्के घरों का निर्माण, प्रत्येक गरीब को बिजली और पानी, किसानों की आय दुगुनी, युवाओं और महिलाओं के लिए पर्याप्त अवसर, जातिवाद, सम्प्रदायवाद और आतंकवाद से मुक्त भारत; जहां भाई–भतीजावाद व भ्रष्टाचार से कोई समझौता न हो तथा देश स्वराज के सपनों को साकार करने में सक्षम हो, की 'राष्ट्र की सामूहिक इच्छा' का आह्वान किया। कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता है कि लोगों की सामूहिक इच्छा के बिना राष्ट्र भरोसे के साथ प्रगति और विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने अपील की कि राष्ट्र को एक-साथ मिलकर अथक रूप से 2017 से 2022 तक पांच वर्षों तक काम करना होगा, ताकि नए भारत का सपना साकार हो सके। उन्होंने ठीक ही कहा कि यदि हमें उज्ज्वल भारत के सपने को साकार करना है, तो 125 करोड़ लोगों की 'टीम इंडिया' को 'न्यू इंडिया' के लिए वचनबद्ध बनना होगा। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

न गाली से, न गोली से, परिवर्तन होगा गले लगाने से: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को 71वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली समस्त महान विभूतियों का स्मरण किया। साथ ही उन्होंने यह बात भी रेखांकित की कि वर्तमान वर्ष निश्चित तौर पर विशेष है, क्योंकि यह भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ, चम्पारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ और बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित "सार्वजनिक गणेश उत्सव" के समारोह की 125वीं वर्षगांठ है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने वर्ष 1942 और 1947 के बीच सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिसकी परिणति भारत की स्वाधीनता के रूप में हुई। उन्होंने कहा कि हमें वर्ष 2022 तक एक नये भारत के सृजन के लिए समान सामूहिक दृढ़ निश्चय और संकल्प का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने विशेष बल देते हुए कहा कि हमारे देश में सभी एक समान हैं और हम आपस में मिलकर गुणात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए 'चलता है' दृष्टिकोण को छोड़ "बदल सकता है" नजरिया अपनाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने जीएसटी पर अमल को सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि आज गरीब वित्तीय समावेश की पहल के जरिए मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि सुशासन का वास्ता निश्चित तौर पर प्रक्रियाओं की तेज गति और सरलीकरण से है। जम्मू-कश्मीर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा, "न गाली से, न गोली से, परिवर्तन होगा गले लगाने से।"

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है तथा सर्जिकल स्ट्राइक ने इसे रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर भारत की हैसियत बढ़ रही है और कई देश आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं। विमुद्रीकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश और गरीबों को लूटा है, वे चैन से सो नहीं पा रहे हैं और आज ईमानदारी का जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने विशेष बल देते हुए कहा कि कालेधन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और प्रौद्योगिकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी।

उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे डिजिटल लेन-देन को और ज्यादा बढ़ावा दें।

प्रधानमंत्री ने नये भारत के अपने विजन का उल्लेख करते हुए कहा, "तंत्र से लोक नहीं, लोक से तंत्र चलेगा।' प्रधानमंत्री ने इस वर्ष रिकॉर्ड फसल पैदावार के लिए किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष 16 लाख टन दालों की खरीदारी की है, जो विगत वर्षों में की गई खरीदारी की तुलना में बहुत अधिक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के बदलते स्वरूप के परिणामस्वरूप आज रोजगार के लिए कुछ भिन्न कौशल की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को कुछ इस तरह से कौशल युक्त किया जा रहा है, जिससे कि वे रोजगार मांगने की बजाय रोजगार सृजित करें।

'तीन तलाक' से पीड़ित महिलाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस परम्परा के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं के साहस की सराहना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति, एकता और सौहार्द का हिमायती है। उन्होंने कहा कि जातिवाद और सम्प्रदायवाद से हमारा भला नहीं होगा। उन्होंने आस्था के नाम पर हिंसा करने वालों की कटु आलोचना की और कहा कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान "भारत छोड़ो" का आह्वान किया गया था, जबकि आज "भारत जोड़ो" का आह्वान करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की गति को मंद किए बगैर ही देश को प्रगति के नये मार्ग पर ले जा रही है।

शास्त्रों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "अनियत कालहा प्रभुतयो विप्लवन्ते", जिसका अर्थ यह है कि यदि हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाएंगे तो हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह "टीम इंडिया" के लिए "नये भारत" का संकल्प लेने का बिल्कुल सही समय है।

उन्होंने एक ऐसे नये भारत के सृजन का आह्वान किया, जिसमें गरीबों के पास अपना मकान होगा, पानी एवं बिजली की सुविधाएं उन्हें सुलभ होंगी, किसान चिंता मुक्त होंगे एवं आज के मुकाबले उनकी आमदनी दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि यह ऐसा नया भारत होगा जिसमें युवाओं एवं महिलाओं के पास अपने सपनों को साकार करने के लिए पर्याप्त अवसर होंगे। उन्होंने कहा कि यह ऐसा नया भारत होगा, जो आतंकवाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद से मुक्त होगा और इसके साथ ही स्वच्छ एवं स्वस्थ भी होगा। प्रधानमंत्री ने शौर्य पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में एक वेबसाइट लांच करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण की मुख्य बातें

- यह वर्ष आजाद भारत के लिए एक विशेष वर्ष है। अभी पिछले सप्ताह ही भारत छोड़ो आंदोलन का 75 साल हमने स्मरण किया। हम चम्पारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं। यह साबरमती आश्रम की शताब्दी का भी वर्ष है। यह वर्ष है लोकमान्य तिलक की उस घोषणा का 125वां वर्ष है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
- 21वीं सदी का भाग्य ये नौजवान बनाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है और अब 18 साल होने पर है। मैं इन सभी नौजवानों को हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं।
- मैं समझता हूं, चलता है का जमाना चला गया, अब तो आवाज यही उठे कि बदला है, बदल रहा है, बदल सकता है; यही विश्वास हमारे भीतर होगा, तो अपने-आप बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है।
- गरीबों को लूटकर के तिजोरी भरने वाले लोग आज चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं और उससे मेहनतकश और ईमानदार व्यक्ति का भरोसा बढ़ता है। आज ईमानदारी का महोत्सव मनाया जा रहा है और बेईमानी के लिए सिर छुपाने की जगह नहीं बच रही है। ये काम एक नया भरोसा देता है। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बेनामी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है।
- 'वन रैंक-वन पेंशन' का अटका हुआ मामला हल किये जाने से हमारे फौजियों की आशा-आकांक्षाएं पूरी हुई हैं जिससे देश के लिए मर-मिटने की उनकी ताकत और बढ़ जाती है।
- आज दुगुनी रफ्तार से सड़के बन रही हैं, आज दुगुनी रफ्तार से रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही हैं, आज 14 हजार से ज्यादा गांव, जो आजादी के बाद भी अंधेरे में पड़े हुए थे, वहां तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है और देश उजाले की तरफ बढ़ रहा है।
- वक्त बदल चुका है। आज सरकार जो कहती है वो करने के लिए संकल्पबद्ध नजर आती है। चाहे हमने इंटरव्यू खत्म करने की बात की हो, चाहे हमने प्रोसेस को खत्म करने की बात की हो।
- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देश हमें सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। हमारे वैश्विक संबंध भारत की शांति एवं सुरक्षा में भी एक नया आयाम जोड़ रहे हैं।
- जम्मू-कश्मीर का विकास, जम्मू-कश्मीर की उन्नति, जम्मू-कश्मीर के सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करने का प्रयास, ये जम्मू-कश्मीर की सरकार के साथ-साथ, हम देशवासियों का भी संकल्प है। कश्मीर समस्या 'न गाली से सुलझने वाली है, न गोली से। यह समस्या हर कश्मीरी को गले लगा कर के सुलझने वाली है। सवा सौ करोड़ का यह देश इसी परम्परा से पला बढ़ा है।
- आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आतंकवादियों को बार-बार हमने कहा है कि आप मुख्यधारा में आइये। भारत के लोकतंत्र में आपकी बात करने के लिये पूरा अधिकार है, पूरी व्यवस्था है।
- जब कोई भी काम अटक जाता है, रुक जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरे गरीब परिवारों को होता है। हमने रूकी हुई परियोजनाओं पर ध्यान दिया है। इन चीजों में बदलाव लाने के लिए हमने नई-नई टैक्नोलोजी Geo-Technology, Space-Technology, इन सारी चीजों को जोड़ करके हमने उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया है।
- 'नई इंडिया' हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र है। हम 'नई इंडिया'

में उस लोकतंत्र पर बल देना चाहते हैं जिसमें तंत्र से लोक नहीं, लेकिन लोगों से तंत्र चले, ऐसा लोकतंत्र 'नई इंडिया' की पहचान बने, उस दिशा में हम जाना चाहते हैं।

- नोटबंदी में सवा सौ करोड़ देशवासियों ने जिस धैर्य को दिखाया, उसी का परिणाम है कि हम आज भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल लगाने में एक के बाद एक कदम उठाने में सफल हो रहे हैं।
- देश में दाल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। हिन्दुस्तान में सरकार द्वारा दाल खरीदने की परंपरा नहीं रही है, इस बार जब मेरे देश के किसानों ने दाल उत्पादन करके गरीब को पौष्टिक आहार देने का काम किया, तो सरकार ने 16 लाख टन दाल खरीदने का ऐतिहासिक कार्य किया।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शुरू की गई योजानाओं में से 21 योजना हम पूर्ण कर चुके हैं और बाकी 50 योजनाएं आने वाले कुछ समय में पूर्ण हो जाएंगी। 2019 के पहले कुल 99 बड़ी-बड़ी योजनाएं को परिपूर्ण करके किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम हम पूर्ण कर देंगे।
- भारत सरकार ने 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' लागू की है। जिसके कारण उन व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाएगा जो बीज से बाजार तक किसान की मदद करेंगे।
- रोजगार से जुड़ी योजनाओं में, ट्रेनिंग के तरीके में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार, मानव संसाधन विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक नई योजनाएं हाथ में ली हैं। नौजवानों को बिना गारंटी बैंकों से पैसा मिले इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया है।
- पिछले तीन वर्ष में 6 IIT, 7 नए IIM, 8 नए IIIT, इसका निर्माण किया है और शिक्षा को नौकरी के अवसरों के साथ जोड़ने का काम भी हमने किया है।
- पूरे देश में तीन-तलाक के खिलाफ एक माहौल बना है। मैं इस आंदोलन को चलाने वाली बहनों को, जो तीन-तलाक के खिलाफ लडाई लड़ रही हैं, हृदय से उनका अभिनदंन करता हूं और मुझे विश्वास है कि माताओं-बहनों को अधिकार दिलाने में, उनकी इस लड़ाई में देश उनकी पूरी मदद करेगा।
- हमारा भविष्य निर्माण करने के लिए हमारी माताओं, बहनों का योगदान बहुत बड़ा होता है, और इसलिए Maternity Leave जो 12 सप्ताह की थी, वो 26 सप्ताह, उसमें आय चालू रहेगी, इस प्रकार से देने का काम किया है।
- कभी-कभी आस्था के नाम पर धैर्य के अभाव में कुछ लोग ऐसी चीजें कर बैठते हैं, जो समाज के ताने-बाने को बिखेर देती हैं। आस्था के नाम पर हिंसा का रास्ता, इस देश में कभी भी चल नहीं सकता, यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, उस समय 'भारत छोड़ो' का नारा था, आज नारा है 'भारत जोड़ो'।
- भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक बड़ा अहम काम है, हम उस पर बल देने का प्रयास कर रहे है। सरकार बनने के बाद पहला काम किया था SIT बनाने का। आज तीन साल के बाद मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, गर्व से बताना चाहता हूं कि तीन साल के भीतर-भीतर, करीब-करीब सवा लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कालाधन को हमने खोज दिया है, उसको पकड़ा है और उसको surender करने के लिए मजबूर किया है।
- नोटबंदी के द्वारा हमने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। अभी जो रिसर्च हुआ है, करीब तीन लाख करोड़ रुपए...। ये सरकार ने रिसर्च नहीं की है, बाहर के एक्सपर्ट ने की है। नोटबंदी के बाद तीन लाख करोड़ रुपए, बैंकिंग सिस्टम में वापस आए है।
- 01 अप्रैल से 05 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले नए व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 56 लाख। पिछले साल इसी अवधि में ये संख्या सिर्फ 22 लाख थी। दुगुने से भी ज्यादा ! ये कारण कालेधन के खिलाफ हमारी लड़ाई का परिणाम है। नोटबंदी के बाद जब data-mining किया गया। तीन लाख ऐसी कंपनियां पाई गईं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ shell कंपनियां हैं। हवाला का कारोबार करती हैं। तीन लाख, कोई कल्पना कर सकता है। और उसमें से पौने दो लाख का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया है। देश का माल लूटने वालों को जवाब देना पड़ेगा, ये काम हमने कर के दिया।
- हम युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और वे रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं।
- विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्ग हमारे देश में है–आईटी का जमाना है, आइए हम डिजिटल लेन की दिशा में आगे बढ़े।
- शास्त्रों में कहा गया है अनियत कालाः प्रवृत्तयो विप्लवन्ते – सही समय पर अगर कोई कार्य पूरा नहीं किया, तो मन चाहे नतीजे नहीं मिलते। इसलिए टीम इंडिया के लिए न्यू इंडिया के संकल्प का सही समय यही है।
- हम देश को विकास के नए मार्ग पर पूरी गति के साथ ले जा रहे है।
- राष्ट्र शांति, एकता और सद्भाव के साथ आगे बढ़ रहा है।
- हम पूर्वी भारत, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दे रहे है। इन क्षेत्रों का तेजी से विकास करना होगा।
- हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे, जहां गरीब के पास पक्का घर होगा, बिजली होगी, पानी होगा।
- हम सब मिलकर एक ऐसा देश बनाएंगे जहां देश का किसान चिंता में नहीं, चैन से सोएगा, आज वो जितना कमा रहा है, उससे दोगुना कमाएगा।
- हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे, जहां युवाओं और महिलाओं को उनके सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर मिलेंगे।
- हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जो आतंकवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद से मुक्त होगा।
- हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे, जहां भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से कोई समझौता नहीं होगा।
- हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और स्वराज के सपने को पूरा करेगा।
- हम एक दिव्य और भव्य भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। ■

भ्रष्टाचारियों को संरक्षित और पोषित करती है सिद्धारमैया सरकार: अमित शाह

एक बहुदलीय लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में किसी भी पार्टी का मूल्यांकन तीन मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए-पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी का सिद्धांत और सत्ता में आने पर सरकार की कार्यपद्धति। अब समय आ गया है कि देश की जनता इन आधारभूत मापदंडों पर राजनीतिक पार्टियों का मूल्यांकन करे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 अगस्त को आईटीसी गार्डेनिया, बेंगलुरु (कर्नाटक) में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और कार्यपद्धति पर विस्तार से चर्चा की। विदित हो कि श्री शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय दौरे पर कर्नाटक में थे। इससे पहले कैम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर एयरपोर्ट टोलगेट के निकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात् वे बेंगलुरु स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय 'जगन्नाथ भवन' पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन किया। पार्टी कार्यालय में उन्होंने प्रदेश कोर कमिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। तत्पश्चात् उन्होंने भाजपा सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद् के सदस्यों के साथ अलग से बैठक की। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करने से पूर्व उन्होंने होटल आईटीसी गार्डेनिया में प्रदेश पदाधिकारियों, विभागों के प्रभारियों व सहप्रभारियों, विभागों के संगठन सचिवों, जिला अध्यक्षों, जिला महासचिवों, मोर्चा अध्यक्षों, मोर्चा महासचिवों एवं प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों के साथ भी विचार-विमर्श किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एक बहुदलीय लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में किसी भी पार्टी का मूल्यांकन तीन मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए-पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी का सिद्धांत और सत्ता में आने पर सरकार की कार्यपद्धति। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश की जनता इन आधारभूत मापदंडों पर राजनीतिक पार्टियों का मूल्यांकन करे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी

सभी पार्टियों से अलग है, क्योंकि आज देश में मौजूद लगभग 1650 छोटी-बड़ी पार्टियों में से केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर आतंरिक लोकतंत्र बचा हुआ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यदि पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है तो वह देश का भला नहीं कर सकती, देश के लोकतंत्र नहीं रक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि देश की अधिकतर पार्टियों में सबको पता है कि उसका अगला अध्यक्ष कौन होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, जेडी (एस) का अगला अध्यक्ष कौन होगा, यह सब लोगों को पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य कौन होगा, यह किसी को मालूम नहीं है। इसका कारण यह है कि भाजपा में अध्यक्ष किसी परिवार में जन्म लेने के आधार पर नहीं, बल्कि अपने कृतित्व के आधार पर बनते हैं।

श्री शाह ने कहा कि किसी भी दल का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है-पार्टी का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को समझने के लिए जन संघ की उत्पत्ति किन परिस्थितियों पर गौर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जन संघ की स्थापना उस वक्त हुई थी जब सत्ता प्राप्त का दूर-दूर तक कोई सवाल नहीं था। उन्होंने कहा कि भारतीय जन संघ की स्थापना ही सिद्धांतों के आधार पर देश को एक वैकल्पिक नीति देने

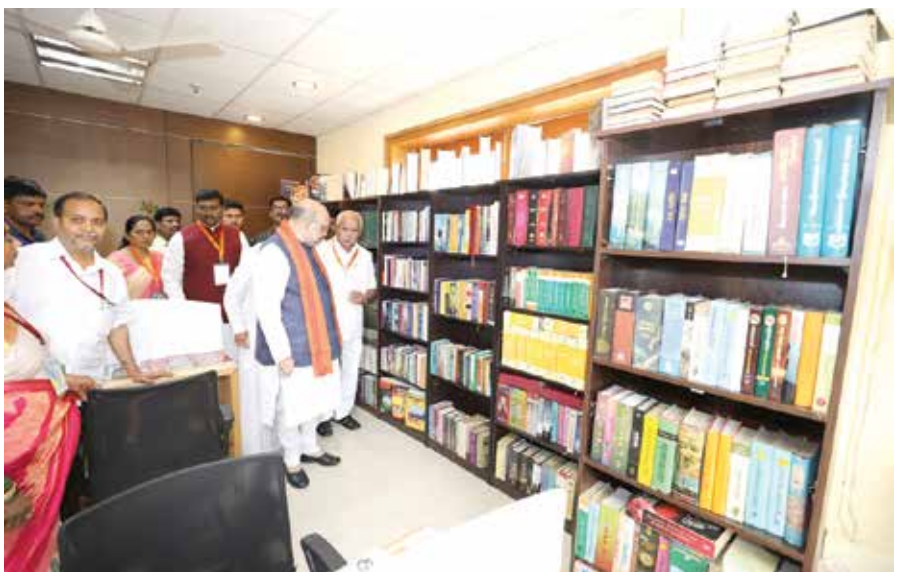

के लिए हुई थी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नेहरू जी के नेतृत्व में जब देश की विकास नीति, कृषि नीति, विदेश नीति, अर्थ नीति, रक्षा नीति और शिक्षा नीति का निर्माण हो रहा था, तब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित कई राष्ट्र मनीषियों को लगा कि नेहरू सरकार देश के लिए जो नीतियां बना रही है, उन नीतियों के रास्ते पर यदि यह देश चलता रहा तो पीछे मुड़ने का भी रास्ता नहीं मिलेगा, तब उन लोगों ने एक ऐसी वैकल्पिक नीति को राष्ट्र के सामने रखने का साहस किया जिसमें देश की मिट्टी की सुगंध हो, उससे पाश्चात्य विचारों की बू न आती हो और जो नीतियां देश को विकास के पथ पर गतिशील करने में सहायक हो। उन्होंने कहा कि 1950 से 2017 की जन संघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा अंत्योदय, एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यात्रा रही है और यही हमारे मूल सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा कि अंत्योदय से हमारा मतलब है - विकास की दौड़ में पीछे छूट गए समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की दौड़ में खड़े सबसे पहले व्यक्ति के बराबर लाना।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में मूल अंतर यह था कि कांग्रेस देश की पुरातन विरासत और संस्कृति को ख़त्म कर देश का नवनिर्माण करना चाहती थी, जबकि जन संघ देश की पुरातन विरासत और संस्कृति के आधार पर देश का पुनर्निर्माण करना चाहती थी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि याद कीजिये 2014 से पहले के समय को जब देश में कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन की सरकार थी, इस सरकार ने 10 वर्ष में लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले हुए, अर्थव्यवस्था की हालत बदतर थी, युवाओं में आक्रोश था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, हर तरफ अराजकता का माहौल था। उन्होंने कहा कि आज देश में तीन साल से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन तीन सालों में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है और तीन सालों में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाए हैं।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के विकास व गरीब-कल्याण के लिए लगभग 106 योजनाओं की शुरुआत की है और इनमें से एक भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी एक जो किसी एक वर्ग विशेष के लिए बनी हो। ये सभी योजनायें सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी हैं। उन्होंने कहा कि 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर भारत अंतरिक्ष के अंदर दुनिया की एक प्रमुख ताकत के रूप में उभरा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के लगभग पौने तीन करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस सिलिंडर पहुंचाया गया है, साढ़े चार करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है और लगभग 29 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोल कर उन्हें देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से देश के करोड़ों गरीब युवाओं को स्वरोजगार

के अवसर उपलब्ध कराये गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के रूप में 'एक राष्ट्र, एक कर' का स्वप्न साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, बेनामी संपत्ति क़ानून, शेल कंपनियों के खिलाफ अभियान और मॉरीशस-साइप्रस-सिंगापुर रूट को बंद करके काले-धन पर कठोर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग को पूरी दुनिया में स्वीकृति दिलाकर देश की संस्कृति को प्रतिष्ठित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा, स्वायल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, सिंचाई योजना, ई-मंडी जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तब इस तरह की गरीब-कल्याण की सोच विकसित होती है और प्रधानमंत्री जी ने देश की सोच के स्केल को ऊपर उठाने का काम किया है।

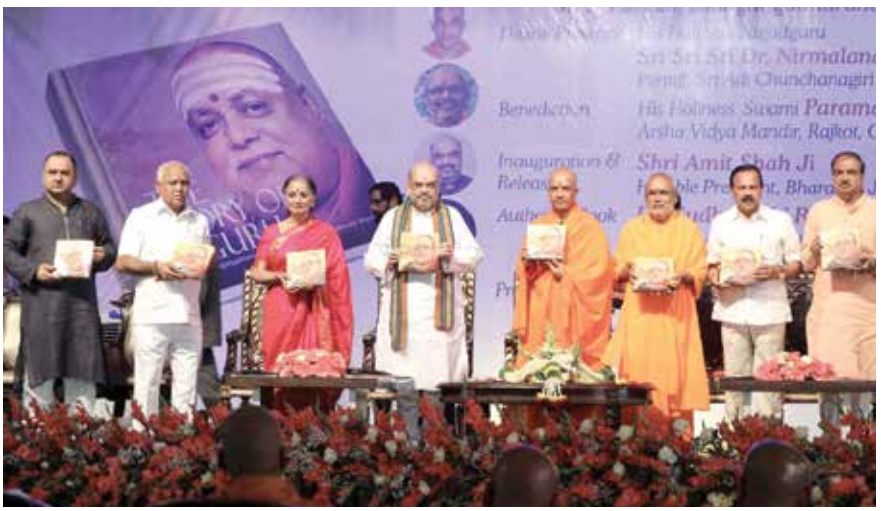

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लोगों तक पहुंचने ही नहीं देती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार देश की भ्रष्टतम सरकार है, मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में ऐसी भ्रष्ट सरकार कहीं नहीं देखी। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते भ्रष्टाचारियों को संरक्षित और पोषित करती है, उन्हें दंडित नहीं करती। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के दोषियों को दंडित किया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि तीन साल में मोदी सरकार ने कर्नाटक के विकास के लिए काफी कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में केन्द्रीय करों में कर्नाटक की हिस्सेदारी केवल 61,691 करोड़ रुपये थी, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में इसे लगभग ढाई गुना बढ़ाकर 1,86,925 करोड़ रुपये कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 13वें वित्त आयोग में कर्नाटक को 11,518 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई थी, जबकि मोदी सरकार में कर्नाटक के लिए 16,291 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में भी 478 करोड़ की वृद्धि करते हुए 1145 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय कर्नाटक को लोकल बॉडीज ग्रांट के तौर पर केवल 6,534 करोड़ रुपये मिलते थे, जबकि मोदी सरकार ने इसमें ढाई गुना वृद्धि करते हुए 15,145 करोड़ रुपये आवंटित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कर्नाटक को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तौर पर कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में छः गुने से अधिक की राशि दी है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने 13वें वित्त आयोग में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के रूप में कर्नाटक को मात्र 271 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई थी, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में इसके लिए 1,645 करोड़ रुपये आवंटित किये। उन्होंने कहा कि केवल इन पांच योजनाओं में ही मोदी सरकार ने कर्नाटक के लिए 219506 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में ढाई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कई केन्द्रीय योजनाओं में हजारों करोड़ रुपये की राशि कर्नाटक को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कर्नाटक को विकास के लिए इतना पैसा दिया, लेकिन फिर भी कर्नाटक विकास में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? राज्य की जनता को सिद्धारमैया सरकार से इसका जवाब जरूर मांगना चाहिए। आप इसका हिसाब मांगें या न मांगें, मैं तो जरूर मांगूंगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार का विकास रूपी ट्रान्सफॉर्मर जल चुका है, इसे बदलने का वक्त आ गया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मेलन में उपस्थित प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ऐसी चुनी जानी चाहिए जो जनता की भलाई के लिए काम करे। उन्होंने निवेदन करते हुए कहा कि कर्नाटक का विधान सभा चुनाव आने वाला है, आप इसमें मूक प्रेक्षक न बनें, मूक प्रेक्षक बनने से राज्य का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य में विकास को प्रवाहित करने वाली सरकार के निर्माण में भागीदार बने। उन्होंने प्रबुद्ध जनों से अपील करते हुए कहा कि आगामी कर्नाटक विधान सभा चुनाव में प्रदेश के विकास के लिए आप राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन करें और श्री येदुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाएं। ■

नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार जीत

हाल ही में तीन राज्यों-मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र-में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली। मध्य प्रदेश में 43 नगरीय निकाय अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में भाजपा को 25 सीटों पर विजय मिली, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने माकपा-कांग्रेस को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया, वहीं मीरा-भायंदर महानगरपालिका चुनाव में पार्टी ने 95 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना परचम लहराया।

मध्य प्रदेश

भाजपा ने जीती 25 सीटें

मध्य प्रदेश में 43 नगरीय निकाय अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर विजय मिली, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 15 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। वहीं, तीन सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए। इन 43 नगरीय निकाय के लिए 11 अगस्त को मतदान हुआ था। 16 अगस्त को परिणाम आए। इनमें चार नगरपालिकाओं के अध्यक्ष एवं 39 नगर परिषदों के अध्यक्ष शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने फिर शानदार सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई

देते हुए जनता का आभार माना और कहा कि यह विजय भाजपा की नीतियों की विजय है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता है। उनके नेतृत्व और विकास की जीत है। यह जीत कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम की जीत है। ■

पश्चिम बंगाल

भाजपा बनी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी

पश्चिम बंगाल हुए नगर निकाय चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को सभी सात निकायों में जीत मिली, जबकि वामदलों और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी अधिकतर स्थानों पर दूसरे स्थान पर रही।

गत 17 अगस्त को आए चुनाव परिणाम में भाजपा ने तीन नगर निकायों में छह सीटें जीतीं, जिनमें उत्तर बंगाल के धूपगूड़ी में चार और बुनियादपुर (उत्तर बंगाल) तथा दक्षिण बंगाल के पंसकुरा में एक-एक सीट शामिल है। तृणमूल ने भी पंसकुरा और पूर्वी मिदनापुर- जिला के हाल्दिया, बीरभूम के नलहाटी, दक्षिण दिनाजपुर के बुनियादपुर और जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी सहित ने बर्धमान पश्चिम जिला के दुर्गापुर, कूपर्स कैम्प में जीत दर्ज की है।

चुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि इस चुनाव में भाजपा तृणमूल कांग्रेस की मुख्य विपक्षी बनकर उभरी है। वामदल की सहयोगी फॉरवर्ड ब्लॉक का इस चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन रहा। बहरहाल, उन्होंने नलहाटी नगर पालिका में एक सीट जीती। वहीं माकपा और कांग्रेस इस चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही।

महाराष्ट्र

भाजपा की बड़ी जीत

मीरा-भायंदर महानगरपालिका चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की। इस चुनाव में भाजपा ने 95 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2012 में हुए चुनाव में पार्टी ने आधी सीटों पर सीट दर्ज की थी। शिवसेना की झोली में 22 सीटें आई, जबकि 2012 में सेना को 14 सीटें मिली थीं।

भाजपा की इस जीत पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं और मीरा रोड और भायंदर के वोटरों का धन्यवाद किया है। गौरतलब है कि मीरा-भायंदर चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि 2012 के चुनाव में एनसीपी 26 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। वहीं कांग्रेस को 10 सीटों से संतोष करना पड़ा, जो 2012 के मुकाबले 10 सीट कम है। भाजपा की बड़ी जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया।

सरकार ने घुटना प्रत्यारोपण के उच्चतम मूल्य निर्धारित किए

लोगों को इससे 1500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत होगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2017 के अवसर पर दिए गए भाषण में की गयी घोषणा के अनुसार सरकार ने 16 अगस्त से ही घुटने की शल्य-चिकित्सा में प्रयुक्त आर्थोपेडिक प्रत्यारोपणों के उच्चतम मूल्य निर्धारित किए हैं। यह जानकारी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। भारत में प्रतिवर्ष किए जाने वाले लगभग 1 से 1.5 लाख आर्थोपेडिक घुटना प्रक्रियाओं की संख्या के आधार पर इससे भारत के लोगों को प्रतिवर्ष लगभग 1500 करोड़ रुपये की बचत होगी। उन्होंने कहा कि यह अनैतिक मुनाफाखोरी को रोकने और आखिरी आदमी के लिए सस्ती और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

श्री कुमार ने कहा कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार इस व्यापार में बहुत मुनाफा था, जो अनुचित और अनैतिक मुनाफाखोरी के रूप में व्याप्त था। एनपीपीए ने उच्चतम मूल्य निर्धारित करते हुए सभी नई प्रौद्योगिकी प्रत्यारोपणों को ध्यान में रखते हुए ये मूल्य निर्धारित किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

घुटना प्रत्यारोपण की किस्म	पहले औसत अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये)	औसत रूप से घटाए गए मूल्य	नए उच्चतम मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये)
कोबाल्ट क्रोमियम (व्यापक रूप से प्रयुक्त)	1,58,324	65%	54,720
विशेष धातु जैसे टाइटेनियम और ऑक्सीडाइज्ड ज़िरकोनियम	2,49,251	69%	76,600
उच्च लचीलापन प्रत्यारोपण	1,81,728	69%	56,490
संशोधित प्रत्यारोपण	2,76,869	59%	1,13,950
कैंसर और ट्यूमर के लिए विशिष्ट प्रत्यारोपण	कंपनी विशिष्ट मूल्य; एनपीपीए द्वारा 1,13,950 रुपये निर्धारित किए जाने हैं।		

श्री अनंत कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 तक

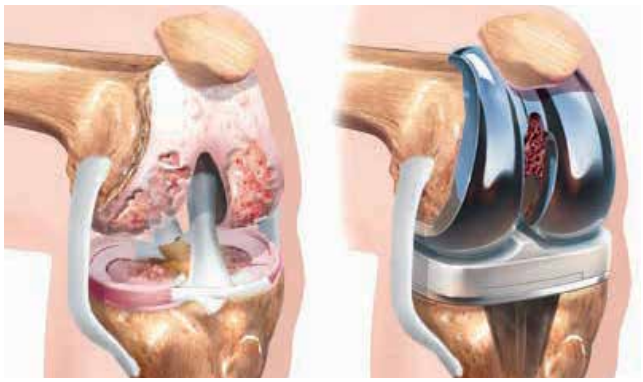

ऑस्टियोआर्थराइटिस दुनिया में गतिहीनता का चौथा सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। भारत में 1.2 से 1.5 करोड़ ऑर्थोपेडिक मरीज हैं, जिन्हें आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता है। अधिकांश निदान किए गए लोगों को घुटने की सर्जरी की आवश्यकता हैं, लेकिन वह अधिक कीमत के कारण ऐसी सर्जरी कराने में असमर्थ है। सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए आज से ही घुटने के प्रत्यारोपण के अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रहे हैं।

भारत में 1.2 से 1.5 करोड़ ऑर्थोपेडिक मरीज हैं, जिन्हें आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता है। अधिकांश निदान किए गए लोगों को घुटने की सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन वह अधिक कीमत के कारण ऐसी सर्जरी कराने में असमर्थ हैं।

श्री अनंत कुमार ने बताया कि सरकार को सभी आयातकों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, अस्पतालों आदि सहित सभी हितधारकों से इस बारे में पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद है, ताकि घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों में की गयी इस कमी का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने यह भी बताया कि मुनाफाखोरी की सभी शिकायतों की कड़ाई से निगरानी की जाएगी और ली गई अधिक राशि दोषी पार्टियों से 18% ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ऐसी पार्टियों के लाइसेंस रद्द करने और ऐसी अनैतिक मुनाफाखोरी में लगे हितधारकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बारे में भी विचार कर सकती है। ■

उदय में भाग लेने वाले राज्यों ने अपने डिस्कॉम का 2.09 लाख करोड़ रुपये का ऋण अधिगृहित किया

उज्ज्वल डिस्कॉम बीमा योजना (उदय) नवंबर, 2015 में शुरू की गई थी और इसने अपनी शुरुआत का एक वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है। उदय में भाग लेने वाले राज्यों ने 2015-2016 तथा 2016-2017 वर्षों के लिए उदय में दिए एफआरबीएम अधिनियम में उधारी में छूट के अंतर्गत अपने डिस्कॉम्स का 2.09 लाख करोड़ का लक्षित ऋण अपने हाथ में ले लिया है।

लक्षित ऋणों को अपने हाथ में लेने तथा उन्हें एसडीएल बॉन्ड जारी करने की राज्यों की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। अब भागीदार डिस्कॉम्स को लगभग 37 हजार करोड़ रुपये के बांड जारी करने हैं, जो यथा समय कर दिए जाएंगे। डिस्कॉम का बाकी ऋण कैपेक्स ऋण के रूप में है, जो स्वयं भुगतान करता है अथवा स्कीम आधारित ऋण, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से अनुदान में परिवर्तित होता है। अतः राज्यों को उन्हें अधिगृहीत करने की आवश्यकता नहीं है।

ऊपर बताए गए ऋण तथा अन्य परिचालनिक हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप भागीदार डिस्कॉम्स ने मार्च 2017 तक लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की शुद्ध बचत हासिल की है। इसके अलावा भागीदार राज्यों में आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)–औसत राजस्व जारी (एआरआर) का अंतर प्रति यूनिट करीब 14 पैसे कम हो गया है तथा वित्त वर्ष 2017 में एटी एंड सी के घाटे में तकरीबन 1 प्रतिशत की कमी आई है।

उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य अब डिस्कॉम के घाटों का अधिग्रहण ग्रेडेड तरीके से शुरू करेंगे, जिसकी शुरूआत चालू वित्त वर्ष से वित्त वर्ष 2017 के घाटे के 5 प्रतिशत अधिग्रहण से होगी। केन्द्र, राज्यों तथा डिस्कॉम द्वारा सहकारिता तथा प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की भावना से किए गए सतत, समेकित तथा सहक्रियात्मक प्रयास से वित्त वर्ष 2019 तक वितरण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। ■

इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह के लिए फास्ट टैग की उपलब्धता सुगम करने हेतु उठाए गए कई कदम

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह के लिए फास्ट टैग की उपलब्धता सुगम के लिए आरबीआई और एनपीसीआई के साथ विचार विमर्श के बाद दो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इनमे फास्टटैग की आनलाइन बिक्री और टोल प्लाजा के निकट सर्व सेवा केंद्र (सीएससी)

द्वारा आफलाइन बिक्री सम्मिलित है। फास्टटैग जारी करने वाले बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है और यह खरीदार के घर पर कोरियर के द्वारा पंहुचाया जायेगा।

ऑनलाइन बिक्री के अलावा 18 अगस्त 2017 से फास्ट टैग टोल प्लाजा के निकट सर्व सेवा केंद्र (सीएससी) के बिक्री केंद्र से भी खरीदे जा सकेंगे। सीएससी के पास अपने विशाल नेटवर्क द्वारा कम अवधि में 20 करोड़ आधार कार्ड बनाने और डिजिटल इंडिया में कई उपलब्धियां हासिल करने का रिकार्ड दर्ज है। आशा है कि सीएससी के साथ जुड़ने के बाद इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह (ईटीसी) को ओर बल मिलेगा। सभी टोल प्लाजा में आरएफआईडी रीडर को लगाने ओर एकीकरण संबधी हाईब्रिड ईटीसी कार्य प्रगति पर है और इसके 31 अक्टूबर, 2017 तक पूरा होने की संभावना है। सभी हाईब्रिड लेन में से एक को विशेष तौर पर फास्ट टैग वाहनों के लिए आरक्षित रखा जायेगा। इसमें टोल भुगतान का अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जायेगा। फास्ट टैग वाहनों के लिए विशेष लेन की शुरुआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कैशलेश अर्थव्यवस्था की मुहिम के अनुरूप एनएचएआई अपने क्षेत्र में आने वाले सभी टोल प्लाजा में ईटीसी आधारभूत ढांचे की स्थापना और प्रभावी क्रियान्वयन में कार्यरत है। इस दिशा में एनएचएआई द्वारा किए जा रहे कार्य से राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वालों को सुरक्षित और सुगम यात्रा प्रदान की जा सकेगी। ■

माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अव्यपगत पूल के निर्माण की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 16 अगस्त को 'माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (मस्क) के रूप में माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के लिए सार्वजनिक खाते में अव्यपगत (Non-lapsable) पूल के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें 'माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर' की सभी राशियों को जमा किया जाएगा।

मस्क से मिलने वाली समस्त निधियों का प्रयोग पूरे देश में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के छात्रों के लाभार्थ योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। उपरोक्त निधि के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित के लिए भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपरोक्त पूल का प्रशासन और रख-रखाव उपकर से प्राप्त राशि को माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा की चल रही योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा।
- तथापि मानव संसाधन विकास मंत्रालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यकता पर आधारित माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा की किसी कार्यक्रम/योजना के लिए निधि का आवंटन कर सकता है।
- किसी वित्तीय वर्ष में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की चल रही योजनाओं पर व्यय प्रारंभ में सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सम्पन्न किया जाएगा और जीबीएस की राशि का इस्तेमाल हो जाने के उपरांत ही मस्क से खर्चों का वित्तपोषण किया जाएगा।
- मस्क का रख-रखाव भारत के लोक खाते के अंग के रूप में गैर-ब्याज आधारित प्रारक्षित निधि के रूप में किया जाएगा। इसका प्रमुख लाभ जहां एक ओर वित्तीय वर्ष के अंत में किसी राशि का परिसमापन न होना सुनिश्चित होगा, वहीं माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों के उपलब्धता के माध्यम से उनकी पहुंच बढ़ सकेगी।

विशेषताएं

प्रस्तावित गैर समापनीय निधि में जमा राशि माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा के विस्तार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा के लिए: वर्तमान में मानव संसाधन मंत्रालय का विचार उपकर से प्राप्त राशि को निम्नलिखित के लिए माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करने का है।

निम्नलिखित सहित चल रही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना तथा अन्य अनुमोदित कार्यक्रम:

राष्ट्रीय संसाधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना

माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए राष्ट्रीय योजना

उच्चतर शिक्षा के लिए: संक्षिप्त राशि निम्नानुसार खर्च की जाएगी:-

- ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधियों में योगदान, कॉलेज विद्यालयों और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की चल रही योजनाएं
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- छात्रवृत्ति (संस्थाओं को प्रखंड अनुदान से) और शिक्षकों और प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय मिशन
- तथापि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आवश्यकता के आधार पर तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के किसी कार्यक्रम/योजना हेतु निधियों का आवंटन कर सकता है।
- माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के लिए उपकर लगाने का प्रयोजन माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना है। इस निधि को प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संचालित किया जाएगा, जहां इस उपकर की शेष राशि को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और मिड डे मील (एमडीएम) के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

पृष्ठभूमि

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान बजटीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए मूलभूत शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टिगत 01.04.2004 की प्रभावी तिथि से सभी केंद्रीय करों पर दो प्रतिशत का शिक्षा शुल्क लगाया गया था। माध्यमिक शिक्षा तथा पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में केंद्र सरकार के इस प्रयास को ऐसा ही बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई। अतएव वित्त मंत्री ने वर्ष 2007 के अपने बजट भाषण में माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के लिए केंद्रीय करों पर एक प्रतिशत का एक और अतिरिक्त उपकर लगाने का प्रयास किया था।

जुलाई 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक कैबिनेट नोट का प्रारूप परिचालित किया गया था, जिसमें माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर की शेष राशि की प्राप्ति के रूप में 'माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष' (मस्क) नामक सार्वजनिक खाते में गैर परिसमापनीय निधि के सृजन का प्रस्ताव किया गया था। संबंधित मंत्रालयों अर्थात् तत्कालीन योजना आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय से इस संबंध में विचार मांगे गए थे। ■

हमारी नीति का लक्ष्य 'प्रत्येक को काम' मिलना चाहिए

दीनदयाल उपाध्याय

जनसंख्या, उसकी आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन एवं व्यवस्था, इन तीनों का पारस्परिक संतुलन जब बिगड़ जाता है, तब अर्थ-संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आज देश की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, किंतु उसके अनुपात में उत्पादन के साधन और उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। फलतः हमारी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पातीं। अतः हमारे रहन-सहन का स्तर बहुत ही नीचा है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हम उत्पादन के साधनों की वृद्धि करके आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करें। इसके लिए हमारी निगाह स्वाभाविक ही पश्चिम के बड़े-बड़े कारखानों द्वारा उत्पादन की ओर जाती है और हम पिछले छह वर्षों से उसके लिए प्रयत्नशील हैं। किंतु प्रश्न उठता है कि क्या उन साधनों पर हम देश के सभी लोगों को काम दे सकेंगे। यदि नहीं, तो उन साधनों के स्वामी एवं उन पर काम करने वाला एक छोटा सा वर्ग रह जाएगा। फलतः उत्पादित वस्तुओं का समान रूप से वितरण नहीं होगा। बचे हुए लोगों को या तो जन-सेवा के कार्यों में लगाना होगा अथवा हमारी आवश्यकताएं इतनी विभिन्न प्रकार की हो जाएं

बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना के साधन जुटाना भी आज हमारे लिए कठिन हो रहा है तथा उस प्रक्रिया में हम छोटे उद्योगों के साधनों को भी नष्ट कर रहे हैं। आज की बेकारी प्रमुखतया 'यांत्रिक' है। यंत्र मनुष्य की जगह लेता जा रहा है तथा मनुष्य बेकार होता जा रहा है। यंत्र का अर्थ प्रगति समझा जाता है और इसलिए हमारी प्रगतिवादी मनोवृत्ति 'यंत्रीकरण' से विमुख नहीं होने देती है। हमें इस संबंध में समन्वयात्मक दृष्टि से काम करना होगा। हमारी नीति का आधार होना चाहिए 'प्रत्येक को काम'।

कि हम उनकी पूर्ति के लिए सबको खपा सकें तथा उसके साधन जुटा सकें। यह भी संभव है कि हम कानून बनाकर जहां चार लोगों से काम चल जाए वहां दस लोग रखने की सलाह दें। यह प्रजातांत्रिक देश में व्यापक रूप से संभव नहीं है। बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना के साधन

जुटाना भी आज हमारे लिए कठिन हो रहा है तथा उस प्रक्रिया में हम छोटे उद्योगों के साधनों को भी नष्ट कर रहे हैं। आज की बेकारी प्रमुखतया 'यांत्रिक' है। यंत्र मनुष्य की जगह लेता जा रहा है तथा मनुष्य बेकार होता जा रहा है। यंत्र का अर्थ प्रगति समझा जाता है और इसलिए हमारी प्रगतिवादी मनोवृत्ति 'यंत्रीकरण' से विमुख नहीं होने देती है। हमें इस संबंध में समन्वयात्मक दृष्टि से काम करना होगा। हमारी नीति का आधार होना चाहिए 'प्रत्येक को काम'।

प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसे काम मिले। काम न मिलने से उसकी व्यक्तिगत आजीविका का सहारा तो जाता ही रहता है, वह राष्ट्र की संपत्ति अर्जन में सहयोग देने से भी वंचित हो जाता है। प्रत्येक को काम का सिद्धांत यदि स्वीकार कर लिया तो 'समवितरण' की दिशा निश्चित हो जाती है। अर्थ के केंद्रीकरण के स्थान पर हम विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते हैं।

'प्रत्येक को काम' का सिद्धांत स्वीकार करने पर बातों का भी निर्धारण हो सकेगा। गणित के छोटे से सूत्र के रूप में हम अर्थशास्त्र का सिद्धांत रख सकते हैं-

जxकxय=इ

यहां 'इ' समाज की प्रभावी इच्छा का द्योतक है, जिसकी पूर्ति की उसमें शक्ति है।

'ज' समाज के काम करने योग्य व्यक्तियों का द्योतक है।

'क' काम करने की अवस्था एवं व्यवस्था का द्योतक है।

'य' यंत्र का द्योतक है।

इस सूत्र के अनुसार यदि हम चाहते हैं कि 'ज' निश्चित रहे तो 'इ' के अनुपात में 'क' और 'य' को बदलना होगा। ज्यों-ज्यों हमारी मांग बढ़ती जाएगी, हमें ऐसे यंत्रों का उपयोग करना होगा, जिसके सहारे हम अधिक उत्पादन कर सकें। आज शासन जिस नीति पर चल

रही है, उसमें 'य' सबका नियंत्रण कर रहा है।

वास्तव में तो 'इ' प्रभावी मांग के बढ़ने से ही हमारी समस्या हल होगी, किंतु 'इ' सहज ही नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यह हमारी क्रयशक्ति पर निर्भर करता है। अतः शासन को देश की क्रयशक्ति बढ़ाने का प्रयत्न भी करना होगा।

क्रयशक्ति मूलतः अधिक उत्पादन होने पर ही बढ़ सकती है, किंतु उसके लिए धन के अधिकाधिक समवितरण की एवं आय की विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। आय जब एक सीमा से अधिक हो जाती है तो उसमें क्रयशक्ति नहीं रह जाती है। वहां तो व्यक्ति का लोभ धन के लिए होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन नहीं। साथ ही, समाज के विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों में जब विषमता कम होती है तो एक- दूसरे की चढ़ा-ऊपरी में क्रियाशक्ति और क्रयशक्ति बढ़ती है। यदि यह विषमता बहुत अधिक हुई तो प्रतिस्पर्धा नष्ट होकर भाग्यवाद और संतोष का सहारा लेकर कर्महीनता उत्पन्न करती है। अतः हमारी कर-नीति एवं अर्थ-नीति इन विषमताओं को दूर करें। यह तो अच्छा है कि जमींदारी और जागीरदारी प्रथाएं मिट रही हैं, किंतु आज भी भूतपूर्व राजे-महाराजाओं के पास अपार धन एवं आय के प्रचुर साधन हैं। उनका प्रिवीपर्स जो कि प्रतिवर्ष 5 करोड़ से अधिक होता है, ग़रीब भारत के ऊपर भार है। उनको अभी तक आय कर भी नहीं देना पड़ता। राष्ट्रपति, राज्यपालों, मंत्रियों तथा अन्य शासनाधिकारियों को भी भारी तनख्वाहें दी जा रही हैं। इन्हें कम करना होगा। कर-नीति भी निम्न और मध्यम वर्ग के ऊपर भार बढ़ा रही है। बिक्री-कर इस दृष्टि से अत्यंत अप्रगतिगामी है। इस नीति में भी परिवर्तन करना होगा।

'इ' अर्थात् प्रभाव मांग देश में तथा देश के बाहर भी हो सकती है। यदि हमारा माल बाहर जाता है तो 'इ' बढ़ जाती है। बाहर से माल आने पर देश की वस्तुओं की दृष्टि से 'इ' कम हो जाती है, क्योंकि हमारी 'क्रयशक्ति' का बहुत बड़ा भाग बाहर से आई वस्तुओं की खरीद पर खर्च हो जाता है। आज यही हो रहा है। सरकार की आयात नीति के कारण हमारे बाज़ार विदेशी माल से पट गए हैं। उनके सस्ते और अच्छे होने तथा 'स्वदेशी' प्रेम के अभाव के कारण उनकी भारी खपत है। फलतः स्वदेशी वस्तुओं के लिए 'इ' दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। चूकि 'य' और 'क' में एकाएक परिवर्तन करना संभव नहीं, इसलिए 'ज' कम होता जा रहा है। बेकारी बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए जहां एक ओर विदेशी आयात की उन वस्तुओं पर जो स्वेदशी तैयार माल पर अनुचित रूप से दबाव डाल रही हों, प्रतिबंध लगाना होगा तो दूसरी ओर समाज में 'स्वदेशी' की भावना को भी जाग्रत करना होगा। विदेशी आयात पर नियंत्रण, आयात-निर्यात नीति एवं तटकर-नीति के द्वारा किया जा सकता है। बड़े-बड़े उद्योगों को संरक्षण देने की नीति को शासन ने अंग्रेज़ी काल से ही अपनाया है, किंतु घरेलू एवं ग्रामोद्योगों की ओर दृष्टि पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें संरक्षण की नितांत आवश्यकता है और वह हमें देना ही होगा। ■

(दीनदयाल उपाध्याय समग्र खण्ड-१ से साभार)

'स्वस्थ बच्चे-स्वस्थ भारत' कार्यक्रम का शुभारंभ

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 21 अगस्त को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यक्रम "स्वस्थ बच्चे-स्वस्थ भारत" का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय के 12 लाख से अधिक छात्रों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती कार्ड बनाये जाएगे। श्री प्रकाश जावेडकर ने कोच्चि के अलुआ में स्थित केन्द्रीय विद्यालय नाड में आयोजित कार्यक्रम में इस कार्ड का अनावरण किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रकाश जावेडकर ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य सामान्य शिक्षा को सशक्त कर देश में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना है। सरकार का लक्ष्य सभी के लिए गुणवत्ता परख शिक्षा सुनिश्चित करना भी है। केरल में स्थित केन्द्रीय विद्यालय ने अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक गुणवत्ता प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अधिक सम्मिलित करने की प्रणाली बनाने की आवश्यकता है।

समारोह के दौरान श्री प्रकाश जावेडकर ने केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों से बातचीत भी की। समारोह में जिलाधिकारी श्री मोहम्मद वाई शफीरुल्ला और केन्द्रीय विद्यालय के अपर आयुक्त श्री यू एन खावरे के साथ-साथ अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी भाग लिया। इस दौरान स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत प्रदर्शनी और बच्चों द्वारा योग का प्रदर्शन भी किया गया।

"स्वस्थ बच्चे-स्वस्थ भारत" कार्यक्रम में विभिन्न क्षमताओं और सभी आयु वर्ग वाले बच्चों को विस्तृत और सम्मिलित रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया जायेगा। कार्यक्रम का लक्ष्य अध्यापकों और माता पिता को बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के महत्त्व पर जागरूक करने के साथ-साथ हर दिन एक घंटा खेलने के प्रति प्रोत्साहित करना है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम में ओलम्पिक और पैरालंपिक के मूल्यों को आत्मसात करने का लक्ष्य भी रखा गया है। बच्चों के बीच बचपन को फिर से वापस लाने, शारीरिक गतिविधियों और मनोरंजनात्मक खेलों को शिक्षण पद्धति का अहम भाग बनाने, विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आंकड़ों को एकत्र और विश्लेषण करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कार्यक्रम के उदेश्यों में सम्मिलित है। ■

आचार्य विनोबा भावे

(11 सितंबर 1895-15 नवम्बर 1982)

शत-शत नमन!

श्री विनोबा भावे एक महान् समाज सुधारक, लेखक एवं 'भूदान यज्ञ' आन्दोलन के संस्थापक थे। वे विद्वान एवं विचारशील व्यक्ति थे। उन्होंने वेद, वेदांत, गीता, रामायण, क़ुरआन, बाइबिल आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों का गंभीर अध्ययन-मनन किया।

विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर, 1895 को गाहोदे, गुजरात में हुआ था। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे विनोबा ने 'गांधी आश्रम' में शामिल होने के लिए 1916 में हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। गांधी जी के उपदेशों ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया।

विनायक की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। हाई स्कूल परीक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। बड़ौदा में ग्रेजुएशन करने के दौरान ही विनायक का मन वैरागी बनने के लिए अति आतुर हो उठा। 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर दिया और काशी नगरी में वैदिक पंडितों के सानिध्य में शास्त्रों के अध्ययन में जुट गए।

बहुआयामी व्यक्तित्त्व

अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विनोबा जल्द ही हाफ़िज़-ए-क़ुरआन बन गए। मराठी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बंगला, अंग्रेज़ी, फ्रेंच भाषाओं में तो वह पहले ही पारंगत हो चुके थे। विभिन्न भाषाओं के तकरीबन पचास हजार पद्य विनोबा को कंठस्थ थे। समस्त अर्जित ज्ञान को अपनी

आचार्य विनोबा भावे के विचार

- जिस राष्ट्र में चरित्रशीलता नहीं है उसमें कोई योजना काम नहीं कर सकती।
- ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहां न आदर है, न जीविका, न मित्र, न परिवार और न ही ज्ञान की आशा।
- स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना काम अपने आप कर लेता है।
- विचारकों को जो चीज़ आज स्पष्ट दिखती है, दुनिया उस पर कल अमल करती है।
- केवल अंग्रेज़ी सीखने में जितना श्रम करना पड़ता है उतने श्रम में भारत की सभी भाषाएं सीखी जा सकती हैं।
- कलियुग में रहना है या सतयुग में यह तुम स्वयं चुनो, तुम्हारा युग तुम्हारे पास है।

ज़िंदगी में लागू करने का उन्होंने अप्रतिम एवं अथक प्रयास किया।

विनोबा भावे एक महान् विचारक, लेखक और विद्वान थे। वे एक बहुभाषी व्यक्ति थे। वह एक उत्कृष्ट वक्ता और समाज सुधारक भी थे। विनोबा भावे ने गीता, क़ुरआन, बाइबल जैसे धर्म ग्रंथों के अनुवाद के साथ ही इनकी आलोचनाएं भी की। वे भागवत गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वे कहते थे कि गीता उनके जीवन की हर एक सांस में है। उन्होंने गीता को मराठी भाषा में अनुवादित भी किया।

भूदान आन्दोलन

'भूदान आंदोलन' का विचार 1951 में जन्मा, जब वे आन्ध्र प्रदेश के गांवों में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने भूमिहीन लोगों के लिए ज़मीन मुहैया कराने एक ज़मींदार ने एक एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव किया। इसके बाद वह गांव-गांव घूमकर भूमिहीन लोगों के लिए भूमि का दान करने की अपील करने लगे इस दान को गांधीजी के अहिंसा के सिद्धान्त से संबंधित कार्य बताया। आचार्य भावे ने लोगों को 'ग्रामदान' के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें ग्रामीण लोग अपनी भूमि को एक साथ मिलाकर सहकारी प्रणाली के अंतर्गत पुनर्गठित करते। आपके भूदान आन्दोलन से प्रेरित होकर हरदोई जनपद के सर्वोदय आश्रम टडियांवा द्वारा उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों में श्री रमेश भाई के नेतृत्व में ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया गया। भावे ने 1975 में पूरे वर्ष भर मौन व्रत रखा। 1979 के एक आमरण अनशन के परिणामस्वरूप सरकार ने समूचे भारत में गो-हत्या पर निषेध लगाने हेतु क़ानून पारित करने का आश्वासन दिया। विनोबा भावे का जीवन-दर्शन 'भूदान यज्ञ' (1953) नामक एक पुस्तक में संग्रहीत एवं प्रकाशित किया गया है।

विनोबा को 1958 में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1983 में मरणोपरांत सम्मानित किया।

वृद्धावस्था में विनोबा जी ने अन्न-जल त्याग दिया। आचार्य विनोबा ने कहा कि 'मृत्यु का दिवस विषाद का दिवस नहीं अपितु उत्सव का दिवस' है। अन्न जल त्यागने के कारण एक सप्ताह के अन्दर ही 15 नवम्बर 1982, वर्धा, महाराष्ट्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। ■

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

एक बार में तीन तलाक की प्रथा खत्म

मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन-तलाक प्रथा से पीड़ित उत्तराखंड की शायरा बानो ने सर्वोच्च न्यायालय से भारतीय संविधान के तहत अपने अधिकार के संरक्षण की गुजारिश की थी। इससे सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह मुद्दा आया कि क्या एक ही झटके में तीन बार बोलकर तलाक देने की रवायत मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? इसके बाद से यह मुद्दा जोर पकड़ने लगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में लगातार तीन तलाक का मुद्दा उठाया। गत स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा, "पूरे देश में तीन-तलाक के खिलाफ एक माहौल बना है। मैं इस आंदोलन को चलाने वाली बहनों को, जो तीन-तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है, कि माताओं-बहनों को अधिकार दिलाने में, उनकी इस लड़ाई में देश उनकी पूरी मदद करेगा।"

गत 22 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुसलमानों में 1400 वर्षों से प्रचलित एक बार में तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत के चलन को असंवैधानिक करार देकर निरस्त कर दिया। कोर्ट ने तीन-दो के बहुमत से निर्णय देते हुए कहा कि एक साथ तीन तलाक संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार का हनन है। तलाक-ए-बिद्दत इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संविधान में दी गई धार्मिक आजादी (अनुच्छेद 25) में संरक्षण नहीं मिल सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने शरीयत कानून 1937 की धारा-2 में एक बार में तीन तलाक को दी गई मान्यता निरस्त कर दी।

इस दूरगामी प्रभाव वाले फैसले का सीधा असर यह होगा कि अब भारत में कोई भी शौहर अपनी बीवी को मनमाने ढंग से तलाक-तलाक-तलाक कह कर नहीं छोड़ पाएगा। मुस्लिम महिलाओं के मन में तलाक को लेकर बैठा भय खत्म होगा।

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति यूयू ललित ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक और मनमाना ठहराते हुए निरस्त कर दिया, जबकि प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर व न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर ने अल्पमत से फैसला देते हुए कहा कि तलाक-ए-बिद्दत मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है और इसे संविधान में मिली धार्मिक आजादी (अनुच्छेद 25) में संरक्षण मिलेगा, कोर्ट इसे निरस्त नहीं कर सकता। फैसला देने वाले विभिन्न न्यायाधीशों के बीच मतभिन्नता को देखते हुए बाद में प्रधान न्यायाधीश ने तीन न्यायाधीशों के बहुमत के फैसले को लागू करते हुए तलाक-ए-बिद्दत के प्रचलन को खारिज घोषित किया। ■

> सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है। इससे मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। यह महिला सबलीकरण की ओर शक्तिशाली कदम है।
>
> **– नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

> यह न्यू इंडिया की ओर कदम है। मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमान और समानता के नए युग की शुरुआत है।
>
> **– अमित शाह,** भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

बिहार मंत्रिमंडल विस्तार

बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के अगले दिन राजग मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। गत 29 जुलाई को राज्यपाल श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ने राजभवन के राजेन्द्र मंडप सभागार में आयोजित समारोह में नयी सरकार के 26 मंत्रियों को शपथ दिलायी। शपथ लेने वालों में जदयू के 14, भाजपा के 12 और लोजपा से एक मंत्री ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति श्री हारुण रसीद, बड़ी संख्या में विधायक, विधान पार्षद समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

कोई स्थान ऐसा नहीं रहेगा, जहां भाजपा न हो: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि आज के दौर के भाजपा के कार्यकर्ता अधिक सौभाग्यशाली है, क्योंकि पार्टी अपने सर्वोच्च स्थान पर है लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि 10 से 10 करोड़ सदस्यता वाली पार्टी को बनाने में 1950 से 2017 तक अनेक महानुभावों ने अपना जीवन समर्पित किया है। श्री शाह 18 अगस्त को भोपाल में अपने तीन दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों, प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष आदि की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारे पास आज केन्द्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। 330 सांसद और 1387 विधायक है। हमें आज पार्टी सर्वोच्च स्थान पर दिखायी देती है, लेकिन 2014 की विजय को भी उत्कृष्ट कार्यकर्ता सर्वोच्च नहीं मानता है। इसलिए हमें इससे बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा कि विजय आलस्य भी प्रदान करती है और विजय भूख भी बढ़ाती है। इसलिए हमने विजय की अतृप्त कामना की है। देश में कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं रहे जहां हमारा ध्वज न हो। इसके लिए संगठन को और चुस्त दुरूस्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन किसी चतुराई से नहीं त्याग, तपस्या और बलिदान से आगे बढ़ा है। हमारे संगठन की नींव में चरित्र है। जिस पर यह भव्य और दिव्य इमारत खड़ी है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक कोई बूथ ऐसा नहीं रहे, जहां हम न हो। उन्होंने कहा कि देश ने हमारे ऊपर बहुत भरोसा किया है, इसलिए हमें भी अपने नागरिकों के भरोसे पर खरा उतरना है। यह समयानुकूल कार्यपद्धति में अमूलचूल परिवर्तन से संभव होता है। हम जानते है कि कार्यकर्ता हमारी आत्मा है, उसकी एक निर्धारित कार्य संस्कृति है, जो हमारे भीतर गौरव का भाव जगाती है। हम देखते है कि ऐसे ही कार्यकर्ताओं के बलबूते जहां-जहां हमारी सरकारें है वहां हम अंत्योदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में काम कर रहे है।

श्री शाह ने कहा कि पार्टी के भीतर विभाग और प्रकल्पों की रचना बदलते दौर की मांग पूरी करने का उत्कृष्ट माध्यम है। इन विभागों

और प्रकल्पों की सक्रियता और दिशा पार्टी को अंत्यत सुखद अनुभूति प्रदान करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं को अब आराम करने का अधिकार नहीं है। यदि हम इस राष्ट्र में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते है, तो हमें बिना थके बिना रूके अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहना है। हम सत्ता में 5-10 साल के लिए नहीं कम से कम 50 साल के लिए आए हैं। इस मानस के साथ ही हमें आगे बढ़ते जाना है और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि 40-50 साल की सत्ता के माध्यम से इस राष्ट्र में एक व्यापक परिवर्तन हम खड़ा करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह ने मध्य प्रदेश भाजपा के पितृपुरुष स्वर्गीय कुशाभाउ ठाकरे और प्यारेलाल खण्डेवाल जी का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि यहां के कार्यकर्ता ठाकरे जी की दिशा और प्यारेलाल जी के परिश्रम से अभिसिंचित है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट संगठन दिखायी देता है।

इस अवसर पर मंच पर संगठन महामंत्री श्री रामलाल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश संगठन प्रभारी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री थावरचन्द गेहलोत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रभात झा, राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री अनिल जैन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान उपस्थित थे। इस प्रथम बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री श्री अजयप्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने स्वागत भाषण दिया।

प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन

'केन्द्र सरकार ने मप्र को तीन साल में 5 लाख करोड़ दिए'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए मात्र 3 साल में 5 लाख करोड़ की धनराशि दी है। जिससे यहां के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर सुधार आ रहा है। लेकिन क्या श्री अजय सिंह के पास इस बात का कोई जवाब है कि यूपीए सरकार ने इतने वर्षों तक मध्यप्रदेश के लिए क्या किया?

उल्लेखनीय है कि श्री अजय सिंह ने भाजपा अध्यक्ष के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर एक पत्र के माध्यम से यह सवाल पूछा था कि केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए क्या किया है? श्री शाह ने 18 अगस्त को प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में इस पत्र पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता को सीधे सीधे कठघरे में खड़ा कर दिया।

श्री शाह ने कहा कि हम राजनीति में केवल चुनाव जीतने के लिये नहीं आये। केन्द्र में हमारी सरकार बनने के बाद तीन साल में 50 ऐसे काम हुए हैं, जबकि पहले की सरकारों में 50 साल में गिनाने लायक सिर्फ 3 काम होते थे। श्री शाह ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन जैसे बुनियादी काम दृढ-निश्चय से होते हैं। नोटबंदी ऐसा ही एक बुनियादी कदम है, जो भ्रष्टाचार के खात्मे में एक कारगर अस्त्र साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि जन-धन योजना में गरीबों के 29 करोड़ खाते खोले

पं. दीनदयाल की प्रतिमा का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने किया अनावरण

हजारों की संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता साफा बांधकर वाहन रैली में निकले

अल्पसंख्यक मोर्चा की बहनों ने पुष्पवर्षा कर की अगवानी

भोपाल के सैकड़ों सामाजिक संगठनों ने की पुष्प वर्षा

गये हैं। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को 2 करोड़ 80 लाख गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराये गये हैं। स्वच्छता अभियान में देश में अब तक 450 करोड़ शौचालय बनाये गये हैं। श्री शाह ने कहा कि इन सब कदमों से यह जाहिर होता है कि सरकार उसके लिये होती है, जिसके जीवन में अंधेरा होता है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी जैसे मौलिक सुधार का असर पूरा विश्व 5 साल बाद देखेगा। उन्होंने कहा कि 'वन रैंक वन पेंशन' लागू कर 4 करोड़ जवानों को लाभान्वित किया गया है। श्री शाह ने पाकिस्तान में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मई-2018 तक देश के सभी गांव में बिजली पहुँचा दी जायेगी।

श्री शाह ने बेनामी सम्पत्ति के विरुद्ध बनाये गये कानून, गरीबों को सस्ती दवाई की व्यवस्था, हृदय रोग के लिये स्टेन की कीमत को 2 लाख से घटाकर 30 हजार तक लाने का भी उल्लेख किया।

केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के उत्थान के लिए दिया गया योगदानः एक नजर में

मध्यप्रदेश को 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग से ढाई गुना अधिक राशि मिली है। प्रदेश को 13वें आयोग से 134190 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। 14वें वित्त आयोग से यह राशि बढ़कर 344126 करोड़ हो गयी। इसमें केन्द्रीय कर से 3 गुना, अनुदान सहायता में दोगुना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में दोगुना से अधिक

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया आदिवासी बंधु के घर भोजन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 20 अगस्त को भोपाल से सटे सेवनियां गौड़ पहुंचे। उनके पहुंचने से ढ़ाई सौ घरों की बसाहट में जैसे खुशियों की बहार आ गयी। गौड़ बस्ती के आदिवासी बंधु कमल सिंह उइके के खपरेल वाले टूटे-फूटे मकान में कदम रखते हुए गौंड परिवार ने श्री अमित शाह को दोपहर का भोजन कराया। श्री अमित शाह ने गौड़ परिवार के घर के दाल, बाटी, कढ़ी, चावल और परंपरागत मिष्ठान्न सीरा के साथ भोजन किया और कमल सिंह उइके के परिवार का कुशल क्षेम पूछा। कमल सिंह उइके ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह उसके खपरेल वाले घर में भोजन करने आए हैं। यह आदिवासी गौंड समाज के लिए गर्व की बात है।

और स्थायी निकाय अनुदान के अंतर्गत लगभग 4 गुना राशि प्राप्त हुई।

प्रदेश को 14वें वित्त आयोग से 3 वर्ष में 2,06,475 करोड़, केन्द्रीय योजनाओं में निवेश आवंटन के अंतर्गत 31,859 करोड़, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना में 17,500 करोड़, सात खनिज ब्लॉक आवंटन से मिलने वाले कुल अनुमानित राजस्व के रूप में 54,834 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।

केन्द्रीय योजनाओं में आवंटन, निवेश और खर्च के रूप में प्रदेश को मुद्रा लोन के कुल 60 लाख लाभार्थी के अंतर्गत 20,960 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना में 984 करोड़, अमृत मिशन में 2593 करोड़, स्वच्छ भारत शहरी मिशन में 427 करोड़, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये 53 करोड़, शहरी परिवहन के लिये 2.22 करोड़, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में 860 करोड़, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत 68 करोड़, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत 58 मण्डियों को ई-मण्डी बनाने के लिये 11 करोड़, समन्वित सहकारिता विकास योजना में 1794 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के 312 प्रोजेक्ट के 2,56,638 आवास के लिये 3840 करोड़ और वाइल्ड लाइफ बुद्धिस्ट हेरीटेज सर्किट के लिये 267 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना में प्रदेश में कुल 2 करोड़ 61 लाख खाते खुले। इन खातों में 3096 करोड़ रुपये का कुल जमा है। कुल 1.42 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण से प्रतिवर्ष 737 करोड़ की बचत होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में प्रदेश में 26.20 लाख एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क वितरित किये गये हैं।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 143 शहर, 17 हजार 616 गाँव और 11 जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला, प्रधानमंत्री जन-धन, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जन-सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी केन्द्रीय योजनाओं से प्रदेश में लाभार्थी संख्या 5 करोड़ 19 लाख है।

'भाजपा राष्ट्रवाद और संस्कृति के उन्नयन के लिए कृत संकल्प'

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निवास श्यामला हिल्स पर 19 अगस्त को आयोजित संत समागम के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने संतों के प्रति अपनी गहन आस्था व्यक्त करते हुए नमन किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य का क्षण है कि संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ा है। संस्कृति और परम्पराओं को पुनर्स्थापित करने में शक्ति केन्द्रित की है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने योग को विश्व में स्थापित करके भारतीय संस्कृति का दुनिया अनुपम उपहार दिया है। योगाचार्य दुनिया में रोग से ग्रस्त मानवता को निरामय होने का संदेश दे रहे हैं। आज दुनिया समस्याग्रस्त है और समाधान के लिए भारत की ओर टकटकी लगाये देख रही है। भारत विश्व कल्याण की भावना से कार्य कर रहा है। देश में भाजपा सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी होकर पार्टी विस्तार कर रही है।

श्री मोदी के चमत्कारिक व्यक्तित्व पर लिखी किताब ''नरेन्द्र से नरेन्द्र'' का विमोचन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने 1890 में भारत को विश्व गुरू बनने का जो सपना देखा था वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 21 वी सदी में पूरा होता दिख रहा है। आज भारत स्वामी विवेकानंद के बताये रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली सदी भारत की है। श्री शाह भोपाल में 20 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व, दर्शन और उनके मिशन पर प्रखर राजनीतिज्ञ श्री कैलाश नारायण सारंग द्वारा लिखी गई किताब ''नरेन्द्र से नरेन्द्र'' के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। पुस्तक की प्रस्तावना इस सदी के महानायक प्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन ने लिखी है। श्री शाह ने "नरेन्द्र से नरेन्द्र" पुस्तक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पुस्तक के लेखक श्री कैलाश नारायण सारंग एवं सहकारिता राज्यमंत्री श्री विश्वास सारंग ने भी संबोधित किया। ■

सर्वे संतु निरामया: को चरितार्थ करती मोदी सरकार

नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने अपनी सोच का दायरा अमीरों और शहरों से आगे बढ़ाया और उज्ज्वला, उजाला और स्वच्छ भारत जैसी दर्जनों योजनाएं लाकर समाज के उपेक्षित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। जरूरी दवाओं, दिल के छल्ले और घुटने प्रत्यारोपण के दाम कम करना इन्ही प्रयासों का हिस्सा है।

| अमित शाह |

मोदी सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए "घुटना प्रत्यारोपण" और "हृदय रोगियों के स्टेंट के दामों में अभूतपूर्व कमी की है और जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से सामान्य दवाओं की उपलब्धता को गरीबों के लिए सुलभ किया है। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली इत्यादि जैसी मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करना किसी भी लोक-हितकारी सरकार का दायित्व होता है। परन्तु दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के 67 साल के बाद भी भारत का आम नागरिक इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित था उदाहरण के तौर पर कुछ जानलेवा बीमारियों की दवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। परन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 2014 में देश की कमान संभालने के बाद अनेक ऐसे कदम उठाये गए हैं जिससे कुछ महत्त्वपूर्ण दवाइयों और असाध्य रोगों के इलाज के खर्चे में कई गुना कि कमी आयी है और गरीबों को भारी राहत मिली है।

हड्डियों के जोड़ो ख़ास कर घुटनों की बीमारी बढ़ती उम्र के साथ हमारे देश में काफी आम है। वैसे तो योग और व्यायाम से इस परेशानी को काफी हद तक दूर रखा जा सकता है, परन्तु एक सीमा के बाद बिना कृतिम घुटना लगवाने के और कोई रास्ता नहीं बचता है। परन्तु अभी तक घुटने के प्रत्यारोपण का खर्च एक से ढाई लाख तक का था, जो अधिकतम वरिष्ठ और गरीब नागरिकों की पहुंच से बाहर था। केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे वरिष्ठ नागरिकों के मर्म को समझा और National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) के अध्यादेश के द्वारा घुटने प्रत्यारोपण के दाम लगभग एक तिहाई कर दिए है। अब सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले कोबाल्ट क्रोमियम इम्प्लांट की कीमत डेढ़ लाख से घटा कर लगभग एक तिहाई (54,000) कर दी गई है। इसी तर्ज पर घुटने के दूसरे इम्प्लान्ट्स की कीमतों में भी 75% तक की कमी की गई है। अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिक सस्ते दामों में घुटनों का प्रत्यारोपण करा सकेंगे। घुटने प्रत्यारोपण के दाम सस्ते करवाना संवेदनशील मोदी सरकार द्वारा इलाज के दाम कम करवाने के लिए कोई पहला प्रयास नहीं है। केंद्र में सरकार आने के कुछ माह बाद ही जनवरी 2015 में ही मोदी सरकार जन औषधि केन्द्र बनाने की योजना लाई थी। इन केन्द्रों में लगभग 500 जरूरी दवाइयां 50% से लेकर 95%

तक कम दामों में उपलब्ध है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में एक हज़ार से भी अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके और केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है कि देश के प्रत्येक ब्लॉक में यह सुविधा उपलब्ध हो।

ऐसा कहा जाता था कि दिल का रोग सिर्फ बड़े लोगों की बीमारी है क्योंकि गरीब आदमी इसका इलाज कराने में सक्षम नहीं था। पूर्व में एक दिल के छल्ले (Coronary Stent) की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर थी क्योंकि BVS Stent सवा लाख में और BMS Stent तीस हज़ार में मिलता था। नरेन्द्र मोदी सरकार ने गरीबों के इस मर्म को समझा और इनकी कीमतों को लगभग एक चौथाई क्रमशः 31,080 और 7,623 रुपये कर दी, जिससे कि करोड़ों दिल के मरीजों को भारी राहत मिली। पूर्व में सरकारों की सफलता या असफलता का पैमाना सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक विकास दर और शेयर सूचकांक होते थे, जिसके कारण आम आदमी की जरूरतें कही न कही उपेक्षित हो जातीं थीं। अन्यथा ऐसा क्या कारण था कि 2014 के पूर्व खुले में शौच के लिए जाती युवती, रसोई में धुएं से जूझती गरीब महिला, महंगे इलाज से त्रस्त गरीबों और अंधेरे में जीवन व्यापन के लिए बाध्य ग्रामीणों का दर्द किसी ने नहीं समझा। परन्तु नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने अपनी सोच का दायरा अमीरों और शहरों से आगे बढ़ाया और उज्ज्वला, उजाला और स्वच्छ भारत जैसी दर्जनों योजनाये ला कर समाज के उपेक्षित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। जरूरी दवाओं, दिल के छल्ले और घुटने प्रत्यारोपण के दाम कम करना इन्ही प्रयासों का हिस्सा है।

देश के गरीबों एवं बुजुर्गों के सेवार्थ किये जा रहे इन अभूतपूर्व एवं सार्थक प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

देश बदलने की कोशिश

केंद्र सरकार के डिविजिबल पूल में राज्य का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 फीसद कर दिया गया। इसके साथ ही साढ़े सात फीसदी का प्रावधान स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए भी किया गया। कुल मिलाकर केंद्र के खजाने में जमा होने वाली रकम का 70 से 80 प्रतिशत अब राज्यों के खाते में जा रहा है।

प्रकाश जावडेकर

अपने अब तक के कार्यकाल में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने वाली सरकार की छवि जो अर्जित की, वह अर्थव्यवस्था को भी तेजी दे रही है और जीएसटी इसकी सबसे उम्दा मिसाल है। यह कानून सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ कई दौर की मैराथन वार्ताओं के बाद अस्तित्व में आया। यूं तो 75 फीसद बहुमत के साथ विधेयक कानून बन जाता है, लेकिन इसके पक्ष में सौ फीसद समर्थन रहा और मतदान की नौबत ही नहीं आई। सभी की सहमति से जीएसटी का सपना साकार हुआ। सरकार ने सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने के लिए भी तमाम प्रयास किए हैं। इस क्रम में एक अनूठा काम भी किया गया, जिसकी किसी राज्य ने मांग भी नहीं की थी। केंद्र सरकार के डिविजिबल पूल में राज्य का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 फीसद कर दिया गया। इसके साथ ही साढ़े सात फीसदी का प्रावधान स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए भी किया गया। कुल मिलाकर केंद्र के खजाने में जमा होने वाली रकम का 70 से 80 प्रतिशत अब राज्यों के खाते में जा रहा है। वित्तीय मोर्चे पर इतना बड़ा विकेंद्रीकरण पहली बार देखने को मिला है। राज्यों में विश्वास करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहल है।

सरकार ने जनता के विकास के लिए जो अनेक कार्यक्रम शुरू किए उनके मूल में रहे गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित। इन कार्यक्रमों के तहत प्रत्येक के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन करने का काम इस सरकार ने करके दिखाया है। गांवों के लिए सड़क भी बनी, बिजली भी आई और विकास के अन्य मदों में पैसा भी अधिक मिलने लगा। ग्रामीण व्यवस्था को भारत की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अब वहां इंटरनेट सहित अन्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सरकार का पूरा प्रयास है कि गांवों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। गरीब के लिए आवास, मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत रोजगार के नए-नए अवसर पैदा करने से लेकर मुद्रा योजना में तीन करोड़ से अधिक लोगों को चार लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि मुहैया कराने का काम भी मोदी सरकार ने किया है।

किसानों के लिए सप्त सूत्र के तहत अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उपज का बीमा, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, नीम कोटिंग यूरिया उपलब्ध है। इसके साथ ही किसानों को उपज का अच्छा दाम, आसान ऋण और सामाजिक सुरक्षा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य किसानों के

लिए और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़े। इन्हीं सप्त सूत्रों के आधार पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होगी। अब ऐसा होने का विश्वास भी किसानों में जग रहा है।

अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमने सरकारी स्कूलों को ही बेहतर बनाने की मुहिम चलाई जहां लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आने भी लगे हैं। चार-पांच राज्यों ने तो इस पर इतने बेहतर तरीके से अमल किया है कि अभिभावक अब निजी स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में यह रुझान खासा मजबूत है। जवानों के लिए वन रैंक, वन पेंशन यानी ओआरओपी की भी तीस-चालीस वर्षों से लंबित पड़ी मांग को भी सरकार ने मान लिया। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उनमें कौशल होना आवश्यक है और इसलिए शिक्षा के साथ उन्हें कुशल बनाने का काम कौशल विकास मंत्रालय ने किया है। कौशल विकास और मुद्रा योजना के तहत आसान ऋण द्वारा ऐसी अर्थव्यवस्था बनी है जिसमें रोजगार बढ़ा है।

दलितों, वंचितों, पिछड़ों के प्रणेता डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जन्मभूमि, शिक्षा भूमि (लंदन), महापरिनिर्वाण स्थल तथा चैत्य भूमि मुंबई का विकास पंच तीर्थों के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त दिल्ली में उनकी स्मृति और कार्यों को सहेजने के लिए 15 जनपथ पर अंबेडकर फांउडेशन की स्थापना की गई। ओबीसी के लिए पहली दफा ओबीसी आयोग को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, जिससे जुड़े विधेयक को सरकार ने लोकसभा से तो पारित करा लिया, पर दुर्भाग्य से राज्यसभा में विपक्षी दलों के असहयोग से यह थोड़ा लंबित हो गया है। लेकिन हमें विश्वास है कि यह जल्दी ही वहां से भी पास होगा, क्योंकि इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता पक्की है। गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा और

न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ महंगाई पर सरकार ने लगाम लगाई है। उनके लिए सस्ती दरों पर एलईडी, एलपीजी जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए।

अभी जो नई प्रस्तावना देश के समक्ष प्रधानमंत्री ने रखी है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' को इस वर्ष 75 साल हो रहे हैं और 2022 में आजादी के 75 साल होंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर 2017 से 2022 तक देश भर में परिवर्तन के लिए वही माहौल कायम करने की उन्होंने सोची है जो 1942 से 1947 तक था। उस वक्त किसी से भी पूछो, सभी लोग एक ही संकल्प से जुड़े थे कि देश को आजाद बनाएंगे। उसी से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री ने निवेदन किया है कि अब देश को बेहतर बनाएंगे। इस संकल्प के साथ सभी 125 करोड़ भारतीय जुटें और आतंकवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी और गंदगी से मुक्ति का प्रण लें। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हर व्यक्ति अपना संकल्प जोड़े कि मैं देश के लिए परिवर्तन लाऊंगा। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वह मनोवृत्ति बदलने की एक कोशिश है और इसके सकारात्मक परिणाम भी अब दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए जब नोटबंदी हुई तब हर भारतीय ने एक कैश सोसायटी से लेसकैश सोसायटी की ओर कदम बढ़ाए। वैसे ही जब जीएसटी लागू हुआ तो हम आयकर अनुपालन न करने वाली व्यवस्था से अनुपालन करने वाली व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ने लगे हैं। आज करदाताओं की संख्या में 25 फीसदी की वृद्धि हुई है। ये सभी परिणाम बताते हैं कि देश तेजी से बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। लोगों को विश्वास में लेकर और साथ लेकर देश को आगे ले जाने की इसी नीति के कारण हम कह रहे हैं-साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। ■

(लेखक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं) (दैनिक जागरण से साभार)

दीर्घकालीन सिंचाई निधि के लिए 9020 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अगस्त को वर्ष 2017-18 के दौरान आवश्यकतानुसार 9020 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दी। यह राशि नाबार्ड द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत चल रही प्राथमिकता वाली 99 सिंचाई परियोजनाओं और इसके साथ-साथ उनके कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी) के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ऋण के संदर्भ में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर सुनिश्चित करने के लिए बांड जारी करके जुटाई जायेगी।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों (एआईबीपी) के तहत अनेक प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मुख्य रूप से निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण अधूरी पड़ी थी। वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई (एआईबीपी और सीएडी) के अधीन चल रही 99 परियोजनाओं की दिसम्बर 2019 तक कई चरणों में पूरी करने के लिए पहचान की गई थी। बड़ी मात्रा में निधि की आवश्यकता को पूरा करने और इन परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी के तहत पहचान की गई, मौजूदा परियोजनाओं के लिए केन्द्र और राज्यों के हिस्से के वित्तपोषण के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की आरंभिक निधि के साथ नाबार्ड में समर्पित दीर्घकालीन सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के सृजन की घोषणा की थी।

राज्यों के लिए नाबार्ड से ऋण को आकर्षक बनाने के लिए वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान नाबार्ड को प्रतिवर्ष अपेक्षित लागत मुक्त निधियां उपलब्ध कराकर ब्याज की दर 6 प्रतिशत के आस-पास बनाये रखने का निर्णय लिया गया था।

वर्ष 2016-17 के दौरान नाबार्ड ने एलटीआईएफ के तहत कुल 9086.02 करोड़ रुपये की राशि वितरित की, इसमें से 2414.16 करोड़ रुपये पोलावरम परियोजना (ईबीआर घटक के बिना) के लिए जारी किये गये और बाकी 6671.86 करोड़ रुपये पहचान की गई ईबीआर उपयोग वाली परियोजनाओं के लिए जारी किये गये थे। इसके अलावा 924.9 करोड़ रुपये बजटीय प्रावधान के माध्यम से केन्द्रीय सहायता (सीए) के रूप में वितरित किये गये। वर्ष 2016-17 के दौरान नाबार्ड ने ईबीआर के रूप में भारत सरकार की पूर्ण अदायगी वाले बांड के रूप में 2187 करोड़ रुपये की कुल राशि जुटाई थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान एलटीआईएफ के माध्यम से 29 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की जरूरत होगी, जिसके लिए 9020 करोड़ रुपये की ईबीआर अपेक्षित होगी। राज्यों और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान बतायी गयी स्थिति के अनुसार 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या लगभग पूरी होने वाली हैं। इन सभी 99 परियोजनाओं से 2016-17 के दौरान 14 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई संभावना उपयोग की उम्मीद है। वर्ष 2017-18 के दौरान 33 से अधिक परियोजनाएं पूरी होने की संभावना है। पहचान की गई सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने और निर्माण चरण के दौरान बड़ी तादाद में वेतन वाले और अन्य रोजगार अवसरों का सृजन होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 76 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभावना का उपयोग इस क्षेत्र में कृषि परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगा जिसके परिणामस्वरूप फसलों की सघनता, फसल प्रणाली में परिवर्तन, कृषि प्रसंस्करण और अन्य सहायक गतिविधियों के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। ■

सुशासन की संवाहक
मजबूत सांख्यिकीय प्रणाली

सांख्यिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए 1999 में दो विभागों-सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को समेकित कर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की छत्रछाया में लाया गया। सरकारी आंकड़ों के समूचे परिदृश्य की निगरानी के लिए 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का भी गठन किया गया।

| डी.वी. सदानंद गौड़ा |

विकास संबंधी नीतियां बनाने और उनकी निगरानी तथा मूल्यांकन करने में सांख्यिकी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सांख्यिकी की आवश्यकता जन सेवाएं प्रदान करने और उनके बारे में जनता में बेहतर समझ पैदा कर नीतियों के अमल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी पड़ती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ऐसी मजबूत सांख्यिकीय प्रणाली का होना जरूरी है जिससे आंकड़ों का संग्रह, प्रमाणीकरण, संकलन और प्रसार किया जा सके। भारत में इस तरह की सांख्यिकीय प्रणाली की जड़ें कौटिल्य की पुस्तक 'अर्थशास्त्र' और अबुल फज़ल की किताब 'आईन-ए-अकबरी' में खोजी जा सकती हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया और भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली के पिता कहे जाने वाले प्रो. प्रशांत चंद्र महालनवीस ने आधुनिक भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की आधारशिला रखी। मैं प्रो. पी.वी. सुखात्मे के योगदान का भी उल्लेख करना चाहूंगा, खास तौर पर कृषि सांख्यिकी के क्षेत्र में।

सांख्यिकी के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए 1999 में दो विभागों-सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को समेकित कर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की छत्र छाया में लाया गया। सरकारी आंकड़ों के समूचे परिदृश्य की निगरानी के लिए 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का भी गठन किया गया।

इस समय भारत में केन्द्र स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों की पार्श्विक रूप से विकेन्द्रित (लेटरली डीसेंट्रलाइज्ड) प्रणाली है, जबकि केन्द्र और राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच लंबवत विकेन्द्रित (वर्टिकली डीसेंट्रलाइज्ड) प्रणाली कार्य कर रही है। किसी भी विषय पर सांख्यिकीय आंकड़े जुटाने का अधिकार आम तौर पर उस विषय के लिए जिम्मेदार संगठन का होता है। मेरा मंत्रालय केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के माध्यम से सीधे अपने नियंत्रण में आने वाली गतिविधियों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन को सुचारु बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही हम जहां भी सहायता की जरूरत होती है, वहां अन्य एजेंसियों की मदद भी करते हैं।

वर्तमान सरकार ने सरकारी सांख्यिकीय आंकड़ों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार कर सुशासन को लेकर सरकार की वचनबद्धता की फिर से पुष्टि की है। सरकारी आंकड़ों को सार्वजनिक संपत्ति मानने की भावना से मंत्रालय बड़े पैमाने के विभिन्न सर्वेक्षणों के आंकड़े, उपयोग करने वालों को उपलब्ध कराता है। सभी प्रकाशित रिपोर्टें मंत्रालय के वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड की जा सकती हैं, जबकि सर्वेक्षणों के विस्तृत आंकड़े मामूली शुल्क पर शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं आदि को उपलब्ध कराये जाते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सर्वेक्षण के प्रतिभागियों की पहचान का विवरण किसी को न बताया जाए। ऐसा करके प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखने के सिद्धांत का पालन किया जाता है।

मेरे मंत्रालय का राष्ट्रीय प्रतिदर्श (नमूना) सर्वेक्षण संगठन देश भर में विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराता है। पिछले तीन वर्षों में घरेलू पर्यटन खर्च और सेवाओं तथा टिकाऊ सामान पर घरेलू खर्च; गैर-निगमित गैर-कृषि उपक्रमों और उद्यमों पर केन्द्रित सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। 2016-17 में सेवा क्षेत्र के उद्यम केन्द्रित सर्वेक्षण से अनुभव और समझ हासिल करने के बाद उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की तर्ज पर सेवा क्षेत्र का वार्षिक सर्वेक्षण कराने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) घरेलू उपभोक्ता

खर्च और शिक्षा व स्वास्थ्य पर घरेलू सामाजिक खर्च पर सर्वेक्षण करा रहा है। 2018 में दो सर्वेक्षणों की योजना बनायी गयी है जिनमें से एक विकलांगता पर और दूसरा स्वच्छता, आरोग्य और आवास के बारे में होगा। 2019 में किसानों और ग्रामीणों की हालत का अंदाजा लगाने के लिए खेतिहर परिवारों की स्थिति के आकलन के बारे में सर्वेक्षण और ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद जो महत्वपूर्ण पहल कीं उनमें स्वच्छ भारत अभियान भी शामिल है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने मई-जून 2015 के दौरान 3,788 गांवों और 2,907 शहरी ब्लॉकों में स्वच्छता की स्थिति के बारे में त्वरित सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से शौचालयों की उपलब्धता और उन तक पहुंच तथा ठोस व तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के बारे में वास्तविक स्थिति की जानकारी मिली।

भारत में रोजगार और बेरोजगारी के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा संग्रहीत आंकड़े अब पांच साल के अंतराल के बाद उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के महत्व और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नीतियों पर कारगर तरीके से अमल के लिए रोजगार संबंधी आंकड़ों की बार-बार आवश्यकता पड़ती है, हमने 2017 से आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) शुरू किया है। अब शहरी इलाकों के बारे में आंकड़े हर तिमाही में और ग्रामीण इलाकों के वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराये जाएंगे। इस सर्वेक्षण से उद्योगों और व्यवसाय के आधार पर भी श्रमिकों के वितरण के आंकड़े मिल सकेंगे। इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या और मजदूरों की सेवा की स्थितियों के आंकड़े भी इससे प्राप्त हो सकेंगे। इस सर्वेक्षण में हमने क्षेत्र स्तर पर सूचनाएं प्रेषित करने के लिए पेपर शेड्यूल के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके को बदल कर उसके स्थान पर कम्प्यूटर की मदद से व्यक्तिगत साक्षात्कार का तरीका (सीएपीआई) अपनाया है।

आंकड़ों को क्षेत्रीय कार्यकताओं द्वारा क्षेत्र से सीधे टेबलेट्स में डाला जाएगा। इसके लिए विश्व बैंक के सहयोग से मंत्रालय द्वारा विकसित विशेष साफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इस तरह डेटा कलेक्शन और डेटा एंट्री का काम एक साथ होने से समय की काफी बचत होगी। हम समय के साथ साथ आगे इस तकनीक को एनएसएसओ के अन्य सर्वेक्षणों में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं।

हाल में हमने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकलन के मानदंडों में भी संशोधन किया है और इन्हें संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 की अनुपालना की दृष्टि और बेहतर बनाया दिया है। इसके अलावा बजट सत्र का आयोजन हर साल 1 फरवरी 2017 से कर दिये जाने से मेरे मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक और वार्षिक आंकड़े जारी करने के कैलेंडर में संशोधन किया है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक और वार्षिक आंकड़ों और इनसे संबंधित मैक्रो-इकोनोमिक एग्रिगेट्स में भी बदलाव आया है। 2017-18 का बजट पेश किये जाने से पहले ही संबंधित अनुमान उपलब्ध करा दिये गये थे। आधार वर्ष को वर्तमान 2011-12 की जगह 2017-18 करने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे ढांचागत बदलावों को ज्यादा सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का आधार-वर्ष बदल कर 2011-12 कर दिया गया है1 2011-12 को आधार मानकर आईआईपी की नयी श्रृंखला मई 2017 में जारी की गयी। नयी श्रृंखला में प्रविधि बदल दी गयी है, ताकि सूचकांक ज्यादा मजबूत और प्रतिनिधिमूलक हो जाएं। उत्तर देने वाली इकाइयों से आंकड़े एकत्र करने के लिए हम एक वेब पोर्टल बनाने की योजना भी बना रहे हैं। इसके चालू हो जाने से मासिक सूचकांक को जारी करने में मौजूदा 42 दिन के समय को कम किया जा सकेगा।

मेरे मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार वर्ष में भी बदलाव किया है और इसे 2010 की बजाय 2012 कर दिया गया है। संशोधित श्रृंखला जनवरी 2015 में लागू की गयी थी। भारतीय रिजर्व बैंक, देश की मौद्रिक नीति तैयार करते समय मुद्रास्फीति के आकलन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) को महत्वपूर्ण उपाय के रूप में अपनाता है।

औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे ढांचागत बदलावों को ज्यादा सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का आधार-वर्ष बदल कर 2011-12 कर दिया गया है1 2011-12 को आधार मानकर आईआईपी की नयी श्रृंखला मई 2017 में जारी की गयी। नयी श्रृंखला में प्रविधि बदल दी गयी है, ताकि सूचकांक ज्यादा मजबूत और प्रतिनिधिमूलक हो जाएं।

प्रक्रियाओं का मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण डिजायन और अनुसंधान प्रभाग का आईएसओ-9001:2009 प्रमाणन कराया गया है, जो गुणवत्तापूर्ण कार्य-निष्पादन के मानदंडों के अनुपालन का प्रमाणपत्र है। मंत्रालय ई-गवर्नेंस की दिशा में भी प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

उपयोग करने वालों की सुविधा के लिए पिछले साल मंत्रालय का नया वेबसाइट शुरू किया गया, जो निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विकसित और डिजाइन किया गया है।

एनएसएस, एएसआई और आर्थिक सर्वेक्षण के यूनिट स्तर के आंकड़ों के प्रसार के लिए भारतकोष ई-प्राप्ति पोर्टल के गेटवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर-भारतीयों को उपलब्ध कराये जाने वाले आंकड़ों के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मुहैया कराने की प्रक्रिया

जारी है।

एनएसएस, एएसआई और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के प्रसार के लिए वैब आधारित सर्वेक्षण डेटा कैटलॉग/माइक्रो डेटा आर्काइव तैयार किया जा रहा है।

मंत्रालय का कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) पर अमल की देखरेख करता है। यह 150 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली केन्द्र सरकार की परियोजनाओं और बीस सूत्री कार्यक्रम की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

मेरा मंत्रालय एमपीएलएडीएस के बारे में नीतियां बनाने, धनराशि जारी करने और इसकी निगरानी प्रणाली निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। एक नया एमपीएलएडीएस पोर्टल बनाया गया है, जो सभी संबद्ध पक्षों जैसे माननीय सांसदों, राज्यों के नोडल अधिकारियों, जिला अधिकारियों और नागरिकों के उपयोग के लिए है। इस पोर्टल का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नागरिकों को इस योजना

मेरा मंत्रालय ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचे से संबंधित 150 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत की परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब और उनकी लागत में बढ़ोतरी की निगरानी करता है। इसमें परियोजना लागू करने वाली एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाता है।

के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी देना है। एमपीएलएडीएस पोर्टल नागरिकों को माननीय सांसदों के कार्यक्षेत्र में विकास कार्यों के बारे में सुझाव देने का अवसर भी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत किये जाने वाले सभी कार्य, खास तौर पर लंबित परियोजनाएं पूरी हो सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधिकारी राज्यों का दौरा करते हैं और मुख्य सचिव समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य में प्रगति की समीक्षा करते हैं। योजनाएं तैयार करने और इनके अमल में प्रणालीगत सुधारों को शामिल करने तथा सरकारी धन का बेहतरीन उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एमपीएलएडीएस के दिशानिर्देशों में बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन किया गया है। ऐसा करते हुए जनता, माननीय सांसदों, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) समेत सभी संबद्ध पक्षों से प्राप्त सुझावों/फीडबैक का भी ध्यान रखा गया है।

हमारी सरकार कम सुविधा संपन्न लोगों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। एमपीएलएडीएस के तहत सृजित स्थायी महत्व की परिसंपत्तियां यथासंभव विकलांग लोगों के अनुकूल हों, इसके लिए अनिवार्य प्रावधान किये गये हैं। एमपीएलएडीएस के तहत सृजित की जा चुकी स्थायी परिसंपत्तियों में विकलांगों को ध्यान में रखकर रेट्रोफिटिंग कराने की भी इजाजत दी गयी है। एमपीएलएडीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष रूप से स्वीकृत की जाने वाली तमाम चल संपत्तियों, जैसे स्कूल बसों, एम्बुलेंसों आदि का विकलांगों के अनुकूल होना जरूरी है।

मेरा मंत्रालय ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचे से संबंधित 150 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत की परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब और उनकी लागत में बढ़ोतरी की निगरानी करता है। इसमें परियोजना लागू करने वाली एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। ओसीएमएस प्रशासनिक मंत्रालयों, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आयोजित 'प्रगति' बैठकों में परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए ओसीएमएस एक विश्वसनीय उपाय साबित हुआ है। परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए कई अन्य कदम भी उठाये गये हैं। इन उपायों और अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि परियोजनाओं की लागत में बढ़ोतरी मार्च 2014 में 19 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2017 में 11.2 प्रतिशत रह गयी है।

मेरे मंत्रालय ने अपने भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा में कई बड़ी और महत्वपूर्ण पहल भी शामिल हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

पहला, आंकड़ों के संकलन में टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग किया जाएगा, जिसमें क्लाउड सर्वर पर कम्प्यूटर की सहायता से साक्षात्कार की तकनीक और ऑनलाइन वेब पोर्टल शामिल हैं। इनके माध्यम से डिजिटल इंडिया/ई-गवर्नेंस/ई-क्रांति की दिशा में गतिविधियां जारी रखी जाएंगी।

दूसरा, हमने सरकारी सांख्यिकीय आंकडों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय आंकड़ों के बारे में नीति तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने का उद्देश्य आंकड़ों के संग्रह, संकलन और निर्धारित तौर-तरीकों के अनुपालन में एकसमान और पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाकर आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में 100 संकेतकों वाला त्रैमासिक राष्ट्रीय तथ्य पत्रक (फैक्ट शीट) निकालने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने की संभावनाओं का भी पता लगा रहे हैं। इसमें गतिशील और उपयोग करने वालों के लिए अनुकूल डैशबोर्ड पर विभिन्न स्रोत मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह 13 संकेतकों वाली वार्षिक फैक्ट शीट प्रकाशित करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। ■

(लेखक- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री हैं।)

तीन तलाक का खात्मा

| कैलाश विजयवर्गीय |

तलाक, तलाक, तलाक। भारत में मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले इन लफ्जों पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी और गैर इस्लामी बताते हुए रोक लगा दी। तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से भारत में मुस्लिम महिलाओं को अब समाज में बराबरी का दर्जा हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत में पूरे देश में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मुस्लिम महिलाओं को मिले इंसाफ को पूरे देश में जोरदार समर्थन मिला है। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 22 देशों में तीन तलाक को बहुत पहले से गैरकानूनी करार देने के बावजूद भारत में कुछ कट्टरपंथियों ने खुदा का डर दिखाकर मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को जहन्नुम बना कर रखा था।

सप्रीम कोर्ट के फैसले से कुरान की जीत हुई है और तमाम कट्टरपंथियों को जोर का तमाचा लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने के दौरान तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के कलंक से बचाने का वायदा किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की लड़ाई की जीत हुई है। मुस्लिम महिलाओं ने कट्टरपंथियों के इन आरोपों को कि यह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा था, पूरी तरह नकारते हुए मिले इंसाफ पर पूरे देश में मिठाइयां बांटी हैं। मुस्लिम महिलाओं को मिले इंसाफ से भारत में महिला अधिकारों का एक नया युग शुरु हुआ है। तीन तलाक के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली सभी महिलाओं को मुबारकबाद।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। यह मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक प्रदान करता है तथा महिला सशक्तीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली महिलाओं को जीत पर बधाई दी है। यह मुस्लिम महिलाओं के लिए हैरानी की बात है कि 1985 में इंदौर की रहने वाली शाहबानो के अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जीती लड़ाई को संसद में पलटने वाली कांग्रेस के नेता आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। 32 साल तक मुस्लिम महिलाओं को कांग्रेस की महिला विरोधी नीतियों और कट्टरपंथियों का समर्थन करने के कारण दोजख की आग में जलना पड़ा। शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट से मिले इंसाफ को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने एक साल के अंदर मुस्लिम महिला (तलाक में संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, (1986) पारित कर अन्याय में बदल दिया था। इंदौर की रहने वाली मुस्लिम महिला शाहबानो को उसके पति मोहम्मद खान ने 1978 में तलाक दे दिया था। पांच बच्चों की मां 62 वर्षीय शाहबानो ने गुजारा भत्ता पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और पति के खिलाफ गुजारे भत्ते का केस जीत भी लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरज़ोर विरोध किया। कट्टरपंथियों को तो यह फैसला अब नागवार गुजरा है।

1986 में संसद के बल पर कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं के हकों को छीन तो लिया, पर पूरे देश में तब से ही तीन तलाक के खिलाफ मुहिम तेज हो गई थी। बार-बार उठी आवाजों को हुक्मरान कुचलते रहे। मुस्लिम महिलाओं में तीन तलाक के खिलाफ नफरत को मैंने कई बार चुनाव प्रचार के दौरान महसूस किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले चुनाव के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिमों के रहनुमा बनने वाले राजनीतिक दलों को नकार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुरीति से बाहर निकालने के वायदे पर तेज प्रतिक्रिया हुई। मुस्लिम महिलाओं का भाजपा को समर्थन मिला। मार्च 2016 में उत्तराखंड की शायरा बानो नामक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके तीन तलाक, हलाला निकाह और बहु-विवाह की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी। बानो ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन कानून 1937 की धारा 2 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। कोर्ट में दाखिल याचिका में शायरा ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के हाथ बंधे होते हैं और उन पर तलाक की तलवार लटकती रहती है। वहीं पति के पास निर्विवाद रूप से अधिकार होते हैं। तीन तलाक को भेदभाव और बराबरी के अधिकार के खिलाफ बताया गया। सभी मुस्लिम धार्मिक नेता भी मानते हैं कि तीन तलाक कुरान के खिलाफ हैं। माना जाता है कि तीन तलाक की यह कुरीति सऊदी अरब से भारत पहुंची। सऊदी अरब के शेख अपनी अय्याशी के लिए इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। भारत के मुसलमान भी उसी तरह चलने लगे। तीन तलाक के लिए शरीयत का सहारा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों ने तीन तलाक की प्रथा अंसवैधानिक बताया और दो जज इसके विरोध में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह तीन तलाक पर कानून बनाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर छह महीने में कानून नहीं बनाया जाता है, तो तीन तलाक पर शीर्ष अदालत का आदेश जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक देशों में तीन तलाक खत्म किए जाने का हवाला दिया और पूछा कि स्वतंत्र भारत इससे निजात क्यों नहीं पा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में भी मुस्लिम महिलाएं अब बराबरी का अधिकार मिलने के बाद खुली हवा सांस ले सकेंगी। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं)

डिजिटल सशक्तिकरण

भारत की बदलती तस्वीर देखने का अधिकार

2014 के चुनाव से पहले भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को जनांदोलन बनते देखा। ईमानदार सरकार के लिए जनता के आंदोलन की परिणति श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने के रूप सामने आयी है। जनता ने उन पर भरोसा किया, क्योंकि लोगों ने यह परख लिया था कि वह जो कहते हैं उस पर दृढ़तापूर्वक अमल करके पूरा भी करते हैं। श्री मोदी ने अपनी सरकार के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं वे हैं: अतीत के कूड़े की सफाई, अपने वादों पर अमल और सरकारी संस्थाओं पर जनता के भरोसे का फिर से कायम करना।

| पीयूष गोयल |

हर एक सरकार जनता की सेवा करने और देश को रहने योग्य बेहतर जगह बनाने के वादे के साथ सत्ता में आती है। अगर यह वादा भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की वजह से टूटता है, तो देश के नेतृत्व पर से जनता का भरोसा उठ जाता है और लोग जवाब मांगने लगते हैं। चुनावों में जनता खुद ही सरकार को जवाब दे देती है और इसके बाद लोगों की उम्मीदें नयी सरकार पर टिक जाती हैं। इसी तरह के आक्रोष और अपेक्षाओं भरे माहौल में नरेन्द्र मोदी सरकार सत्ता में आयी थी। 2014 के चुनाव से पहले भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को जनांदोलन बनते देखा। ईमानदार सरकार के लिए जनता के आंदोलन की परिणति श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने के रूप सामने आयी है। जनता ने उन पर भरोसा किया, क्योंकि लोगों ने यह परख लिया था कि वह जो कहते हैं उस पर दृढ़तापूर्वक अमल करके पूरा भी करते हैं। श्री मोदी ने अपनी सरकार के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं वे हैं: अतीत के कूड़े की सफाई, अपने वादों पर अमल और सरकारी संस्थाओं पर जनता के भरोसे का फिर से कायम करना।

2014 में जनता ने उस व्यवस्था को नकार दिया था, जिसमें पर्दे के पीछे निर्णय लिये जाते थे और उनकी धुंधली-सी झलक ही 'सूचना के अधिकार' (आरटीआई) के जरिए जनता को देखने को मिल पाती थी। आरटीआई से लोगों के लिए सरकार के कामकाज की ठीक से निगरानी करना मुमकिन नहीं था। दरअसल जनता के अधिकार की बजाय आरटीआई एक ऐसा विशेषाधिकार बन गया था, जो प्रक्रिया संबंधी पचड़ों को ठीक से न जानने वाले बहुत से नागरिकों की पहुंच से बहुत दूर था। जनता को सरकारी कार्य के पूरा हो जाने के बाद ही अजमाये जा सकने वाले हक की जरूरत नहीं थी, बल्कि ऐसे अधिकार की आवश्यकता थी, जो कामकाज में चौबीसों घंटे पारदर्शिता का मौका देता हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशानिर्देश में विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान मंत्रालयों ने अपने निर्णयों, लक्ष्यों और प्रगति को मोबाइल एप

के जरिए डिजिटल रूप में पेश करने का इंतजाम किया है। इस तरह ये मंत्रालय 'बदले हुए भारत के अधिकार' के बारे में प्रधानमंत्री के वादे को पूरा कर रहे हैं।

अन्य साधनों के साथ-साथ हम यूजर फ्रैंडली यानी आसानी से इस्तेमाल किये जा सकने वाले मोबाइल एप के जरिए काम-काज में पारदर्शिता लाने में सफल रहे हैं। आज हमारी तमाम गतिविधियां लोगों के मोबाइल पर उपलब्ध हैं। अगर आप अपने जिले में ऐसे गांवों के बारे में जानना चाहते हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है तो आपको GARV पर लॉगइन करना होगा। आपकी बिजली कंपनी द्वारा चुकाए जा रहे बिजली के दामों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप MERIT पर लॉगइन कर सकते हैं। अगर आपको इस बात की चिंता सता रही है कि आपके इलाके में अगली बार बिजली कब गुल होगी तो बिजली जाने से पहले ही 'ऊर्जा मित्र' आपको पहले ही इसकी सूचना दे देगा।

TAMRA और TARANG विभिन्न परियोजनाओं और उनके लिए सरकार से मिली स्वीकृतियों की स्थिति पर नजर रखते हैं। इनके जरिए जनता परियोजनाओं में आ रही अड़चनों के बारे में सरकार की जवाबदेही तय कर सकती है। यह एक तथ्य है कि 2014 से पहले खानों और खदानों की नीलामी करीब-करीब बंद हो चुकी थी। पिछले तीन वर्षों में सरकार को खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों के 29 खनन ब्लॉकों की बकाया लीज अवधि के दौरान 1.22 लाख करोड़

रुपये से अधिक के राजस्व की आमदनी हुई है। TAMRA एप से इसे और बढ़ाने में मदद मिलेगी। परियोजनाओं की समय पर समाप्ति सुनिश्चित करके TARANG एप ने हमारे विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क के तेजी से विस्तार में भूमिका निभाई है। वर्ष 2014-17 की अवधि के दौरान चालू की जा चुकी परियोजनाओं की लागत वर्ष 2011-12 के दौरान चालू की गयी परियोजनाओं की लागत से 83 प्रतिशत अधिक रही है। इतना ही नहीं 2014-17 के दौरान भारत की विद्युत ट्रांसमिशन क्षमता में 40 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

2015 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश से जनता के मन में बिजली की सुविधा से वंचित देशवासियों के प्रति गहरी संवेदना जगी है। प्रधानमंत्री ने 1,000 दिन के अंदर देश के सबसे दूर-दराज के गांव को भी विद्युतीकृत कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस भगीरथ प्रयास को पूरा करने में जनहित की भावना की बड़ी प्रेरणा रही है। GARV एप ने विद्युतीकरण की दिशा में ग्रामवार प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया और अब GARV II ने उससे भी आगे बढ़कर और परिवार वार आंकड़े उपलब्ध कराकर उसे भी पछाड़ दिया है। पारदर्शिता से हमें बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि जब जनता पड़ताल करने लगती है तो 'स्पीड, स्किल एंड स्केल' (यानी 'रफ्तार, हुनर और पैमाने') के मंत्र में नयी ऊर्जा का संचार हो जाता है। जनता और जन-संचार माध्यमों के जरिए जो जानकारियां मिलती हैं, हम उन्हें बहुत अधिक महत्व देते हैं। GARV से जनता के धन के अपव्यय को रोकने में मदद मिली, क्योंकि इस पर पत्रकारों ने आबादी से रहित गांवों के बारे में जानकारी दी थी। GARV केवल बिजली से वंचित गांवों की सूची ही नहीं दिखाता है, बल्कि इसने आंकड़ों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाते हुए गांवों में इम्पैक्ट स्टडी (यानी विद्युतीकरण के प्रभाव का अध्ययन) का कार्य भी किया है। ग्रामीण विद्युतीकरण का व्यावहारिक स्तर पर असर गांवों में आटा चक्कियों, तरह-तरह के उपकरणों आदि के उपयोग के रूप में देखा जा सकता है।

इससे पहले बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बिजली की खरीद में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था। MERIT और विद्युत प्रवाह नाम के एप ने मनमानी खत्म की है और लागतों में कमी ला दी है। अगले पांच वर्षों में MERIT के जरिए बिजली खरीद की लागत में 20,000 हजार करोड़ की बचत होने की संभावना है जिसका फायदा बिजली बिलों के जरिए आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। UDAY और URJA तो एक कदम और आगे बढ़ गये हैं और कई मानदंडों पर राज्यों/शहरों/वितरण कंपनियों की कारगुजारी का मूल्यांकन कर रहे हैं।

UJALA नाम का एप तो एलईडी बल्बों का सबसे तेजी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित इस एप के पीछे एक कहानी है। उच्चतम न्यायालय ने जब 204 कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द कर दिया तो कोयला ब्लॉकों की नीलामी की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के अंत में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुझ से पूछा कि अब तक कितने एलईडी बल्ब लोगों को बांटे जा चुके हैं। मेरे पास उस वक्त ताजा आंकड़े नहीं थे, इसलिए मैंने कहा कि मैं देखकर बाद में आपको बताऊंगा। उसी वक्त प्रधानमंत्री ने मुझे अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करते रहने और कार्य-निष्पादन के लिए जिम्मेदारी तय करने की याद दिलाई। मैंने तत्काल अपनी टीम को एक ऐसा इंटरनेट पोर्टल तैयार करने का निर्देश जिसमें कोई भी व्यक्ति, कहीं भी और किसी भी जगह से जनता को बांटे गये बल्बों के बारे में जानकारी हासिल कर सके, लेकिन इससे सिर्फ एलईडी बल्बों की संख्या का ही पता नहीं चलता, बल्कि इस तरह के बल्बों के उपयोग से कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में आई कमी, बिजली की बचत और बिजली बिलों में आई कमी से आम जनता के फायदे का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में यह एप इतना लोकप्रिय हो गया कि एलईडी बल्बों की बिक्री की योजना को देश भर में चलाने और इनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने में भी इससे अपूतपूर्व सफलता मिली।

खानों के अंदर क्या होता है इसकी जानकारी देनेवाले माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम यानी MSS एप से अवैध खनन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसी तरह कोल मित्र एप सबसे दक्षतापूर्वक कार्य कर रहे ताप बिजलीघरों का पता चलता है। ARUN एप से जानकारी हासिल कर छत पर सोलर प्रणाली खुद लगाने के साथ-साथ सरकार द्वारा इसके लिए दिये जा रहे प्रोत्साहन, इसकी लागत, स्थापना के तरीके आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। इससे उन बाधाओं को दूर किया जा सकता है, जिनके कारण भारत में छत पर सोलर प्रणालियां लगाने का अभियान क्रांति का रूप नहीं ले पा रहा है।

जितने ज्यादा एप उतना ही ज्यादा उनको डाउनलोड करने का झंझट! आखिर इस भीड़ में से अपने मतलब के एप को कैसे खोजा जाए? जनता को किस तरह से यह बताया जाए कि इस-इस तरह के एप मौजूद हैं? इसके लिए आपको सिर्फ यह करना है कि 1-800-200-300-4 नंबर पर मिस्ड कॉल करें। यह एक साझा नंबर है जिससे कॉल करने वाले को एक लिंक भेजा जाता है जिससे अपने मतलब का एप डाउनलोड किया जा सकता है।

जनता को अपने कामकाज की पड़ताल में भागीदार बनाकर और रीअल टाइम डेटा को सार्वजनिक करके विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान मंत्रालयों ने सरकारी संस्थाओं पर जनता का भरोसा फिर से कायम करने का बीड़ा उठाया है। 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' (अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में हमरा पथ-प्रदर्शन करो)—यह सुंदर और प्रेरणास्पद आदर्श वाक्य इन सभी मंत्रालयों के कर्मचारी गणों को राह दिखाता है। इन एप्स के जरिए हम गोपनीयता और भ्रष्टाचार का अंधेरा हटाना चाहते हैं और ईमानदारी के उजाले की तरफ अग्रसर होकर 125 करोड़ भारतीयों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। ■

(लेखक विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान मंत्रालयों के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।)

एक ऐसा 'न्यू इंडिया' बने, जहां हर व्यक्ति की पूरी क्षमता उजागर हो: रामनाथ कोविंद

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या (14 अगस्त, 2017) पर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। संप्रभुता पाने के साथ-साथ उसी दिन से देश की नियति तय करने की जिम्मेदारी भी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों से निकलकर हम भारतवासियों के पास आ गई थी। कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया को 'सत्ता का हस्तांतरण' भी कहा था, लेकिन वास्तव में वह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। वह एक बहुत बड़े और व्यापक बदलाव की घड़ी थी। वह हमारे समूचे देश के सपनों के साकार होने का पल था - ऐसे सपने जो हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे। अब हम एक नये राष्ट्र की कल्पना करने और उसे साकार करने के लिए आजाद थे।

राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्र भारत का उनका सपना, हमारे गांव, गरीब और देश के समग्र विकास का सपना था। आजादी के लिए हम उन सभी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के ऋणी हैं, जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी थीं। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत छोड़ो आंदोलन की शहीद मातंगिनी हाज़रा जैसी वीरांगनाओं के अनेक उदाहरण हैं।

राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कर्मठ लोगों के साथ सभी को जुड़ना चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लाभ हर तबके तक पहुंचे इसके लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। इसके लिए नागरिकों और सरकार के बीच साझेदारी महत्त्वपूर्ण है:

- सरकार ने 'स्वच्छ भारत' अभियान शुरू किया है लेकिन भारत को स्वच्छ बनाना - हममें से हर एक की जिम्मेदारी है।
- सरकार शौचालय बना रही है और शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन इन शौचालयों का प्रयोग करना और देश को 'खुले में शौच से मुक्त' कराना - हममें से हर एक की जिम्मेदारी है।
- सरकार देश के संचार ढांचे को मजबूत बना रही है, लेकिन इंटरनेट का सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करना, ज्ञान के स्तर में असमानता को समाप्त करना, विकास के नए अवसर पैदा करना, शिक्षा और सूचना की पहुंच बढ़ाना-हममें से हर एक की जिम्मेदारी है।
- सरकार 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के अभियान को ताकत दे रही है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि हमारी बेटियों के साथ भेदभाव न हो और वे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें- हममें से हर एक की जिम्मेदारी है।

- सरकार कानून बना सकती है और कानून लागू करने की प्रक्रिया को मजबूत कर सकती है लेकिन कानून का पालन करने वाला नागरिक बनना, कानून का पालन करने वाले समाज का निर्माण करना - हममें से हर एक की जिम्मेदारी है।
- सरकार पारदर्शिता पर जोर दे रही है, सरकारी नियुक्तियों और सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार समाप्त कर रही है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अंतःकरण को साफ रखते हुए कार्य करना, कार्य संस्कृति को पवित्र बनाए रखना- हममें से हर एक की जिम्मेदारी है।
- सरकार ने टैक्स की प्रणाली को आसान करने के लिए जी.एस.टी. को लागू किया है, प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, लेकिन इसे अपने हर काम-काज और लेन-देन में शामिल करना तथा टैक्स देने में गर्व महसूस करने की भावना को प्रसारित करना- हममें से हर एक की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि देश की जनता ने जी.एस.टी. को सहर्ष स्वीकारा है। सरकार को जो भी राजस्व मिलता है, उसका उपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में ही होता है। इससे किसी गरीब और पिछड़े को मदद मिलती है, गांवों और शहरों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होता है, और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होती है। सन् 2022 में हमारा देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। तब तक 'न्यू इंडिया' के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा 'राष्ट्रीय संकल्प' है। ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

जनधन खातों में नोटबंदी ने दी 9 गुना रकम

रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के दौरान जमा रकम की जानकारी जारी की है। आरबीआई के मुताबिक, पिछले साल 9 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच जनधन खातों में 6600 करोड़ जमा हुए थे, लेकिन नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक इसमें जमा रकम बढ़कर 66,480 करोड़ हो गई। मतलब 50 दिनों में 59,800 करोड़ जमा हुए। इसी तरह दो महीने में जनधन खातों में सामान्य से 9 गुना ज्यादा राशि जमा हुई। निष्क्रिय खातों में भी 9 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच 2830 करोड़ जमा हुए, लेकिन नोटबंदी के 50 दिनों में यह रकम करीब साढ़े सात गुना बढ़ गई।

– नवभारत टाइम्स (18 अगस्त)

दूरसंचार क्षेत्र में 2018 तक 30 लाख नए अवसर

दूरसंचार क्षेत्र वर्ष 2018 तक रोजगार के 30 लाख अवसर सृजित कर सकता है। 4जी प्रौद्योगिकी के तेज विस्तार, बढ़ती डाटा खपत, डिजिटल वॉलेट में वृद्धि और स्मार्टफोन की अधिक स्वीकार्यता से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उद्योग और वाणिज्य संगठन एसोचैम तथा केपीएमजी के अध्ययन मे यह दावा किया गया है। इसमें कहा गया कि दूरसंचार क्षेत्र ऐसी स्थिति में है जहां प्रति उपभोक्ता राजस्व में कमी के बाद भी वे आधारभूत संरचना तथा तकनीकी बेहतरी के लिए निवेश बढ़ाने को मजबूर हैं।

– हिंदुस्तान (18 अगस्त)

ग्रामीण विद्युतीकरण

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। 25 जुलाई, 2015 को योजना की शुरुआत। गांवों में रह रहे गरीबों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का शुरुआती आवंटन। 2800 गांवों का शुरुआती लक्ष्य – एक वर्ष में 7108 गांवों में बिजली पहुंचाई गयी। अभी तक बिजली से वंचित 18,452 गांवों में मई 2017 तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। 14 अप्रैल, 2017 तक बिजली से वंचित 18452 गांवों में से 13,267 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई (72 प्रतिशत)।

– पीआईबी

स्फुट विचार...

यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर एक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख या जाट है। उसे यह याद होना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार है पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं।

-सरदार पटेल

सात घनघोर पाप: काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति,नैतिकता के बिना व्यापार और त्याग के बिना पूजा।

-महात्मा गांधी

पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी जीवन शैली दो अलग-अलग चीजें हैं। चूंकि पश्चिमी विज्ञान सार्वभौमिक है और हम आगे बढ़ने के लिए इसे अपनाना चाहिए, लेकिन पश्चिमी जीवनशैली और मूल्यों के सन्दर्भ में यह सच नहीं है।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

भारत कोई इतना छोटा देश नहीं है कि कोई उसको जेब में रख ले और वह उसका पिछलग्गू हो जाए। हम अपनी आजादी के लिए लड़े, दुनिया की आजादी के लिए लड़े।

- अटल बिहारी वाजपेयी

हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है, जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो आम समाज के लिये मायने रखते हैं।

- मार्टिन लूथर किंग जूनियर

प्रस्तुति: पंकज आनंद

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

71वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलामी देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम के दौरान युवा उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं सॉइल हेल्थ कार्ड्स के विकास की समीक्षा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में नेपाली प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में आईएनएसवी तारिणी पर सवार होकर विश्व जल यात्रा पर जाने वाली भारतीय नौसेना की छह महिला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17